

संस्करण : मुंबई

वर्ष : 10

अंक : 359

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

शनिवार, 03 जनवरी, 2026

जुनून है सच लिखने का

मन्त्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित



3 आवास परियोजनाओं से पुलिसकर्मियों के जीवन... 4 वोट बैंक का लालच बना है पर्यावरण विनाश ... 7 सिडनी में जीत इंग्लैंड टीम के बारे में बहुत...

संक्षिप्त न्यूज

बंगाल सब एरिया में कमान परिवर्तन, मेजर जनरल डीके सिंह ने संभाली जिम्मेदारी

कोलकाता। बंगाल सब एरिया में बुधवार को कमान परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेजर जनरल राजेश ए. मोघे ने औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी मेजर जनरल डीके सिंह को सौंप दी। इस अवसर के साथ ही बंगाल सब एरिया के संचालन और प्रशासनिक नेतृत्व में नया अध्याय शुरू हुआ। मेजर जनरल राजेश ए मोघे 37 वर्ष की विशिष्ट और समर्पित सैन्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान उन्होंने भारतीय सेना में कई अहम कमान और स्टाफ पदों पर सेवाएं दीं। उन्होंने संचालन की तैयारी, प्रशिक्षण व्यवस्था और सैनिकों के कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में विभिन्न इकाइयों ने पेशेवर दक्षता और अनुशासन के उच्च मानक स्थापित किए। कमान परिवर्तन समारोह के दौरान पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने मेजर जनरल राजेश ए मोघे को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य और भारतीय सेना के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने उनके उज्ज्वल योगदान की सराहना करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दीं। लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने बंगाल सब एरिया की कमान संभालने पर मेजर जनरल डीके सिंह को भी बधाई दी। उन्होंने विधास जताया कि मेजर जनरल डीके सिंह अपने व्यापक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और पेशेवर दक्षता के बल पर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि नेतृत्व में निरंतरता, उच्चतम पेशेवर मानक और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उसकी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। बंगाल सब एरिया में यह कमान परिवर्तन उसी परंपरा का प्रतीक है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और सैन्य तैयारियों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

प. बंगाल में सियासी सरगर्मियां:

पीएम मोदी इसी माह कर सकते हैं दौरा! मालदा में बड़ी जनसभा की तैयारी में भाजपा

कोलकाता / नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह राज्य का दौरा कर सकते हैं। प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा मालदा में बड़ी जनसभा की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मालदा और हावड़ा में राजनीतिक सभाएं करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के लोगों को रेलवे की तरफ से मिली सौगातें भी मिलेंगी। पीएम मोदी हावड़ा-गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिहाज से बेहद अहम परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया जा सकता है। **मालदा और हावड़ा में बड़ी जनसभा, जनवरी के तीसरे हफ्ते में चुनावी बिगुल?** प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया कि 17 जनवरी को पीएम मोदी मालदा में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। इसके अलावा 18 जनवरी को हावड़ा में भी भाजपा की विशाल जनसभा हो सकती है। पीएम मोदी का यह दौरा इसी साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद खास माना जा रहा है।

इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, बंगाल पर भाजपा का विशेष ध्यान

बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल के समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। जिन राज्यों में चुनाव



होने हैं उनमें भाजपा शासित राज्य असम, डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार वाले तमिलनाडु भी प्रमुख हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की परीक्षा होगी। इसके अलावा केरल और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। **भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबले के आसार**

सियासी अखाड़े के जानकारों और राजनीतिक पंडितों के मुताबिक बंगाल भाजपा की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से भी इसके संकेत मिलते हैं। बंगाल में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने का दावा करते हुए शाह ने कोलकाता में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि इस साल भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकेगी। ऐसे में दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच दिलचस्प राजनीतिक घमासान देखने को मिलेगा। **बिहार के बाद बंगाल की बारी...** प्रधानमंत्री के साथ शाह की भी पैनी नजर गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक जनादेश के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब बंगाल की बारी है। ऐसे में भाजपा इस विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। बीते

दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता महानगरपालिका के चारों जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी- तृणमूल कांग्रेस के नारे- मां, माटी, মানুষ पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में तीनों ही असुरक्षित हैं। उन्होंने सरकार पर घुसपैठियों के संरक्षण का आरोप भी लगाया। **कटघरे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार, TMC पर कई गंभीर आरोप** शाह ने घुसपैठ के मुद्दे का जिक्र करते हुए भी सत्ताधारी पार्टी को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि घुसपैठिए न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी खतरा बन गए हैं। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल में करोड़ों रुपये के चोटाले होने का दावा करते हुए शिक्षक भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग, नगर निगम समेत कोयला, राशन, मनरेगा और पीएम आवास योजना का जिक्र किया था।

भाजपा और शिवसेना के निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों की राज्य चुनाव आयोग करेगा जांच

मुंबई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर नामांकन को लेकर गुब्बड़ का आरोप लगाया है। राज्य चुनाव आयोग अब इन आरोपों की जांच कर रही है। चुनाव आयोग ने उन नगर निगमों की रिपोर्ट मांगी है जहां उनके उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। आयोग यहां उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनाव जीतने की जांच करेगा। यह जानने की कोशिश करेगा कि कहीं विरोधियों पर नामांकन वापस लेने का दबाव तो नहीं बनाया गया या किसी तरह के लालच और जबरदस्ती तो नाम वापस नहीं करवाए गए। राज्य की 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी के कई उम्मीदवार निर्विरोध जीते ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में पांच भाजपा और चार शिवसेना उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। पिंपरी चिंचवड (पुणे जिले में), जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर नगर निकायों में, कम से कम एक भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है। राज्य चुनाव आयोग का क्या कहना है राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग को सत्ताधारी पार्टियों और चुनाव मशीनरी द्वारा

उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने की शिकायतें मिल रही हैं। कांग्रेस, जनता दल (एस) और आप के उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि मुंबई के कोलाबा में तीन वार्डों में दबाव में उन्हें गैरकानूनी तरीके से नामांकन दाखिल करने से रोका गया। आयोग इन निकायों के नौ वार्डों से अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेगा जहां उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।



आयोग ने बताया हमें नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख, के बाद निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के बारे में रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद, रिटर्निंग अधिकारियों, नगर आयुक्त और संबंधित नगर निगमों के पुलिस आयुक्तों से रिपोर्ट मांगी जाएगी ताकि यह जांच की जा सके कि विरोधियों पर नामांकन वापस लेने के लिए कोई दबाव या लालच दिया गया था या निर्विरोध चुनावों के लिए कोई जबरदस्ती का तरीका इस्तेमाल किया गया था।

तमिलनाडु का 'War on Drugs', CM Stalin ने Modi सरकार से कहा- मिलकर लड़ना होगा

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को तिरुचिरापल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करना आवश्यक है और उन्होंने केंद्र सरकार से देश में मादक पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। तिरुचिरापल्ली में एमडीएमके के संस्थापक वाइको के नेतृत्व में समानता मार्च के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के उन्मूलन की

आवश्यकता पर कोई मतभेद नहीं है, जिसे उन्होंने युवाओं के लिए एक गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है, को जड़ से खत्म करना आवश्यक है अभी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समस्या का समाधान केवल राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता।

‘इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा... पीएम खामोश’, दूषित पानी के मामले पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई 15 मौतों के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर साझा पोस्ट में कहा, ‘इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नंद में रहा। घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं - और ऊपर से ढ़ं नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी; सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार-बार गंदे, बदबुदार पानी की शिकायत की -



फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? **राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल** राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा, ‘सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सल्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये ‘फोकट’ सवाल नहीं - ये जवाबदेही की मांग

है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्यप्रदेश अब कुरुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है - कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब-जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं।’

अभिषेक बनर्जी ने फूँका टीएमसी का सियासी बिगुल, चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर से अपने चुनाव अभियान का आगाज करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) प्रक्रिया के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है। **दिया ‘अबकी बार, फिर जीतवे बंगला’ नारा** बनर्जी ने ‘अबार जीत वे बांग्ला’ (बंगाल फिर जीतेगा) का नारा बुलंद करते हुए दावा किया कि राज्य की जनता आगामी चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने और उन्हें ‘विदाई’ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘भाजपा एसआईआर की आड़ में बंगाल के लोगों के अधिकारों को सीमित करना चाहती है, लेकिन जनता उन्हें करारा जवाब देगी। आज मैं बरुईपुर से इस

महाअभियान की शुरुआत कर रहा हूँ। कल मैं अलीपुरद्वार जाऊंगा और ममता बनर्जी के एक सिपाही के रूप में हर जिले में जाकर जमीनी लड़ाई लड़ूंगा।’



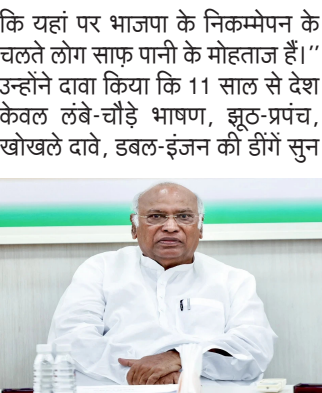
चुनाव आयोग और अमित शाह को चेतावनी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए अभिषेक ने उन्हें ‘वैनिश कुमार’ (गायब करने वाला) करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, ‘तैयार हो जाइए, टीएमसी दिल्ली की ओर बढ़ रही है, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव

आयोग (मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार) पानी में बह जायेंगे। **सुवेदु अधिकारी और ‘हिंदुत्व’ पर सवाल** अभिषेक बनर्जी ने विपक्ष के नेता सुवेदु का हिंदुत्व है? उन्होंने कहा जो लोग रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान करते हैं, वे भला बंगाल को क्या बचाएंगे?’ **मतदाता सूची में हेरफेर का लगाया आरोप** इससे पहले, 31 दिसंबर को अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनावों में धांधली ईवीएम के जरिए नहीं, बल्कि मतदाता सूची में प्रशासनिक हेरफेर करके की जा रही है। उन्होंने हालिया विधानसभा चुनावों (महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार) में भाजपा की 88 प्रतिशत से अधिक ‘स्ट्राइक रेट’ (जीत दर) को अस्वाभाविक बताया। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजद जैसे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा कि वे समय रहते इस प्रणालीगत गड़बड़ी को पहचानने और चुनौती देने में विफल रहे।

अधिकारी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनूस सरकार को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा के अतिरिक्त अन्य कोई भी मौन है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है। खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस मामले पर भी मौन हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है।

इंदौर में हुई मौतों पर भी प्रधानमंत्री हमेशा की तरह मौन हैं: खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत की घटना को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि, “जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस मामले पर भी मौन हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है। खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र मोदी जी, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन स्थापना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि मित्रों, इस संस्थान का नाम मेवाड़ अतीत पर र्व करता है। आज का भारत अपनी परंपराओं का सम्मान करता है



रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली-गाली पर उतर आते हैं। सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। भाजपा सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है।”

खरगे ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। उनका कहना था, “याद दिलाना जरूरी है कि इस मिशन के तहत जल जीवन मिशन का 10 प्रतिशत धन दूषित पानी को साफ करने के लिए दिया जाता है।” कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, “मोदी सरकार और भाजपा ने ना देश को साफ पानी मुहैया कराया है और ना ही स्वच्छ हवा। आम जनता भुगत रही है।” इंदौर के महापौर पृथ्वीमित्र भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। बहरहाल, स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप से छह माह के बच्चे समेत 14 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है। इस दावे की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है।

वंचित वर्गों की याचिकाओं को प्राथमिक सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने चार श्रेणियों में किया वर्गीकरण

नई दिल्ली। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाओं की सूचीबद्धता और सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए चार नई श्रेणियां निर्धारित की हैं। इन श्रेणियों में वित्यागजन और एसिड अटैक पीड़ितों द्वारा दायर मामले, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित याचिकाएं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के मामले तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर रहे लोगों की याचिकाएं शामिल की गई हैं। न्यायालय का कहना है कि

इन वर्गों की याचिकाएं अक्सर भारी संख्या में सूचीबद्ध मामलों के बीच दब जाती थीं। आमतौर पर सोमवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 16 पीठों के समक्ष लगभग 800 नए मामले सुनवाई के लिए आते हैं, जिनमें यह तय किया जाता है कि किन मामलों पर विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। नई व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि कमजोर और वंचित तबकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ जल्द सुनवाई का अवसर मिल सके। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से जारी परिपत्र में वकीलों, पक्षकारों और अन्य हितधारकों से कहा गया है कि नई याचिका दाखिल करते समय यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वह किस श्रेणी में आती है।



एक गठबंधन ऐसा भी! VBA को नहीं मिले उम्मीदवार, कांग्रेस को लौटाई 16 सीटें

दिव्यांश मुंबई(संवाददाता)

मुंबई में आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा है। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) शहर में उसे आवंटित 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में विफल रही है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे की व्यवस्था के तहत, वीबीए को मुंबई में कुल 62 सीटें आवंटित की गई थीं। हालांकि, योग्य उम्मीदवारों की कमी और कई संभावित उम्मीदवारों के दस्तावेजों के अपूर्ण होने के कारण वीबीए इन 16 सीटों पर नामांकन दाखिल नहीं कर पाई। खबरों के मुताबिक, वीबीए ने कांग्रेस नेतृत्व को सूचित कर दिया है कि वह इन 16 सीटों पर चुनाव लड़ने में असमर्थ है और कांग्रेस इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस घटनाक्रम के बाद, कांग्रेस ने मुंबई के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची

मजबूत कर ली है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची बढ़ाई अब तक, कांग्रेस ने मुंबई में 143

सहयोगी दलों जैसे वामपंथी समूहों और राष्ट्रीय समाज पार्टी (आरएसपी) को आवंटित की गई है। कांग्रेस, वीबीए

इसी बीच, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने उन्हें 62 सीटें दी थीं। हम

दोनों ने इस गठबंधन में प्रवेश किया था। जब उन्हें कुछ उम्मीदवार नहीं मिले, तो उन्होंने कुछ सीटें हमें वापस कर दीं। चुनाव के दौरान ऐसी बातें होती रहती हैं। सावंत ने आगे कहा कि पार्टी कितने उम्मीदवार मैदान में उतार पाई है, इस बारे में अंतिम स्पष्टता आज बाद में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद ही सामने आएगी। चूंकि बहुत कम समय बचा था, इसलिए आज जारी होने वाली अंतिम सूची से पता चलेगा कि हम कितने उम्मीदवारों की



उम्मीदवारों की घोषणा की है। वीबीए 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा, गठबंधन की कुछ सीटें अन्य

और अन्य सहयोगी दल मिलकर कुल 195 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी

घोषणा कर सके। हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ पूर्ण समन्वय में आगे बढ़ेंगे।

नरेन्द्र ए. पाटील ने पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारतीय रेल यातायात सेवा के 1995 बँच के अधिकारी नरेन्द्र ए. पाटील ने 01 जनवरी, 2026 को पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, आप पश्चिम रेलवे में मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले आपने पश्चिम रेलवे के मुख्य माल परिवहन प्रबंधक के रूप में भी सेवाएं दीं, जहां आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण रिकॉर्ड माल लदान हासिल किया गया। आपके कार्यकाल के दौरान पश्चिम रेलवे ने अपने इतिहास में पहली बार 100 मिलियन टन माल लदान का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया। इसके अतिरिक्त, आप दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पाटील को भारतीय रेल में 27

वर्षों से अधिक का समृद्ध एवं विविध अनुभव प्राप्त है, जिसमें परिचालन, वाणिज्य, संरक्षा, योजना एवं जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। अपने विशिष्ट कार्यकाल के दौरान आपने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण

बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (जन शिकायतें); मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक; वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक तथा वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जैसे अहम पद शामिल हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (इंजीनियरिंग ग्रेजुएट) पाटील ने कई प्रतिष्ठित व्यावसायिक एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। इनमें INSEAD (सिंगापुर/कुआलालंपुर) तथा लीडर्स इन अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कार्यक्रम शामिल हैं, जो सिंगापुर एवं हांगकांग में आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने आपकी नेतृत्व क्षमता एवं प्रबंधकीय दक्षताओं को और अधिक सुदृढ़ किया। भारतीय रेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पाटील को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय रेलवे (रेल मंत्री) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपको विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2007, 2010 एवं 2013 में महाप्रबंधक पुरस्कार भी प्रदान किए जा चुके हैं।



मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे तथा रेलवे बोर्ड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। आपकी प्रमुख नियुक्तियों में मध्य रेलवे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, रेलवे

रविवार को मध्य रेलवे का मेगा ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेलवे, मुंबई मंडल द्वारा 04.01.2026 को उपनगरीय रेलखंडों पर विभिन्न अभियांत्रिकी एवं रखरखाव कार्यों के लिए निम्नानुसार मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। मुख्य लाइन माटुंगा-मुलुंड अप एवं डाउन धीमी लाइन : 11.05 बजे से 15.55 बजे तक डाउन धीमी लाइन की वे सेवाएं जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 10.14 बजे से 15.32 बजे के बीच रवाना होंगी, उन्हें माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच डाउन तीर लाइन पर मोड़ा जाएगा। ये गाड़ियां सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर ठहरेंगी तथा आगे मुलुंड स्टेशन पर पुनः डाउन धीमी लाइन पर लाई जाएंगी। ये गाड़ियां अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट विलंब से पहुंचेंगी। अप धीमी लाइन की वे सेवाएं जो ठाणे से 11.07 बजे से 15.51 बजे के बीच

रवाना होंगी, उन्हें मुलुंड स्टेशन पर अप तीर लाइन पर मोड़ा जाएगा। ये गाड़ियां मुलुंड और माटुंगा स्टेशनों के बीच अप तीर लाइन पर चलते हुए मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला और सायन स्टेशनों पर ठहरेंगी तथा आगे माटुंगा स्टेशन पर पुनः अप धीमी लाइन पर लाई जाएंगी। ये गाड़ियां भी अपने गंतव्य पर लगभग 15 मिनट

और ठाणे स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन ट्रांस हार्बर लाइन की सभी सेवाएं निलंबित रहेंगी। डाउन लाइन पर वाशी, नेरुल एवं पनवेल की ओर जाने वाली वे सेवाएं जो ठाणे से 10.35 बजे से 16.07 बजे के बीच रवाना होंगी तथा अप लाइन पर ठाणे की ओर जाने वाली वे सेवाएं जो पनवेल, नेरुल एवं वाशी से 10.25 बजे से 16.09 बजे के बीच रवाना



विलंब से पहुंचेंगी। ट्रांस हार्बर लाइन ठाणे और वाशी अथवा नेरुल स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन ट्रांस हार्बर लाइन : 11.10 बजे से 16.10 बजे तक ब्लॉक अवधि के दौरान वाशी अथवा नेरुल

होंगी, रद्द रहेंगी। ये रखरखाव संबंधी मेगा ब्लॉक अवसंरचना के संरक्षण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि इस कारण होने वाली असुविधा के लिए सहयोग एवं धैर्य बनाए रखें।

महायुति सरकार का ऐतिहासिक निर्णय छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के लिए वटू बुद्रुक में ढाई एकड़ भूमि उपलब्ध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की निर्णायक पहल मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। स्वराज्यरक्षक, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की वटू बुद्रुक (तहसील शिरूर) स्थित समाधि स्थल के समग्र विकास के लिए महायुति सरकार ने एक ऐतिहासिक और जनभावनाओं को सम्मान देने वाला निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्पष्ट निर्देशों के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल से पुणे स्थित के.ई.एम. अस्पताल के स्वामित्व की वटू बुद्रुक की भूमि अब समाधि स्थल के विकास हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पुणे जिले के तुलापुर और वटू बुद्रुक विकास आराखड़े में स्थानीय ग्रामवासियों की भावनाओं और सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हीं दोनों ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में २५३२.५१ करोड़ की लागत का भव्य विकास आराखड़ा तैयार किया गया है।

आज जारी शासन निर्णय के अनुसार, के.ई.एम. अस्पताल की वटू बुद्रुक स्थित गट क्रमांक 447 और 448 की कुल 0.87 हेक्टेयर 20 आर भूमि छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि स्थल के विकास कार्यों के लिए तत्काल हस्तांतरित की जाएगी। इसके बदले शासन ने के.ई.एम. अस्पताल को कोढापुरी (तहसील शिरूर) स्थित गट क्रमांक 655 की 0.81 आर भूमि 'भोगवदादार वर्ग-2' के अंतर्गत कब्जा अधिकार सहित प्रदान करने को मंजूरी दी है।

कोढापुरी की यह भूमि अस्पताल को विशेष प्रकार के रूप में राजस्व-मुक्त और भोगवदादार रूप-मुक्त दी गई है। इस भूमि का उपयोग केवल स्वीकृत चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए ही किया

जा सकेगा तथा तीन वर्षों के भीतर वहां कार्य आरंभ करना अनिवार्य होगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान 'धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि स्थल के समग्र विकास की मांग वर्षों से की जा रही थी। इस निर्णय से नियोजित विकास आराखड़े को नई गति मिलेगी। यह समाधि स्थल त्याग, शौर्य और बलिदान का अमर प्रतीक है।' वटू बुद्रुक में प्रस्तावित प्रमुख विकास कार्य। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और इतिहास को दर्शाने वाला अत्यधुनिक संग्रहालय। ऐतिहासिक संदर्भों से समृद्ध भव्य ग्रंथालय। 82 सीटों की क्षमता वाला आधुनिक सभागृह, जहां 10-डी तकनीक के माध्यम से संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक प्रस्तुति दिखाई जाएगी। स्मारक परिसर में विशेष 'अदृश्य शिल्प' भीमा नदी के तट पर 120 मीटर लंबा घाट निर्माण।

पश्चिम रेलवे का ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच शनिवार/रविवार को मेजर ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

ब्रिज नंबर 5 के री-गर्डरिंग कार्य हेतु ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर 13 घंटे का मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक शनिवार/रविवार, 03/04 जनवरी, 2026 को 23:00 बजे से 12:00 बजे तक रहेगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट के बीच अप स्लो लाइन की सभी ट्रेनें अप फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। इसी प्रकार, चर्चगेट और माहिम स्टेशनों के बीच डाउन स्लो लाइन की ट्रेनें डाउन फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें महालक्ष्मी, प्रभादेवी एवं माटुंगा रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी तथा प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण लोअर परेल और माहिम स्टेशनों पर भी ठहराव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें

निरस्त रहेंगी तथा चर्चगेट जाने वाली

ऑपोज़िट दिशा में यात्रा करने की



कुछ ट्रेनों को बांद्रा/दादर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट अथवा रिवर्स किया जाएगा। उपरोक्त ब्लॉक के अतिरिक्त, प्रभादेवी स्थित आरओबी को हटाने के कार्य हेतु डाउन स्लो लाइन पर 23:30 बजे से 07:00 बजे तक 07:30 घंटे का एक और मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान यात्रियों को बांद्रा/दादर से माहिम, माटुंगा रोड, प्रभादेवी, लोअर परेल एवं महालक्ष्मी स्टेशनों तक

आपोज़िट दिशा में यात्रा करने की

वाले यात्री बांद्रा स्टेशन पर उतरकर

उसी टिकट पर ऑपोज़िट दिशा अर्थात अप स्लो लाइन से यात्रा कर सकते हैं। निरस्त की गई ट्रेनों की सूची अनुलग्नक-I में तथा आंशिक रूप से समाप्त/वापस चलने वाली (शॉर्ट टर्मिनेटेड/रिवर्स) ट्रेनों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्टेशन मास्टरों के पास भी उपलब्ध है।

अनुमति होगी। उदाहरणार्थ, चर्चगेट आदि स्टेशनों से महालक्ष्मी, लोअर परेल एवं प्रभादेवी जाने वाले यात्री दादर स्टेशन पर उतरकर उसी टिकट पर ऑपोज़िट दिशा अर्थात अप स्लो लाइन से यात्रा कर इन स्टेशनों तक जा सकते हैं। इसी प्रकार, चर्चगेट आदि से माटुंगा रोड एवं माहिम जाने

www.ircct.co.in वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अनारक्षित डिब्बों के लिए बुकिंग स्टेशन के बुकिंग काउंटरों से तथा यूटीएस (UTS) ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें। इन ट्रेनों के ठहरावों पर विस्तृत समय-सारिणी की जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट देखें या RailOne अथवा NTES ऐप डाउनलोड करें।

कोटा मण्डल-निविदा आमंत्रण सूचना नि.आ.सू.सं.-टीकेडी-34-2025, टीकेडी-38-2025, टीकेडी-39-2025 एवं टीकेडी-40-2025 दिनांक: 31.12.2025 वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता, विद्युत लोको शेड, तुगलकाबाद नई दिल्ली-44, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से, निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिनकी बंद होने की तिथि/समय 23.01.2026 है। निविदाकार बंद होने की तिथि व समय तक अपनी मूल/संशोधित अपनी निविदा आफ्नर जमा कर सकते हैं। मैनुयल निविदा ऑफ्नर स्वीकार नहीं है। विवरण इस प्रकार है :-क्र.सं.-01-निविदा सं.-टीकेडी-34-2025, कार्य का नाम व स्थान-"विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद के श्री फेस लोको में दो वर्षों हेतु पी यू पेंटिंग का कार्य" मात्रा-100 लोको, अनुमानित लागत (रु.में)-45,88,776.00, बयाना राशि (रु.में)-91,800, समापन अवधि-24 माह, क्र.सं.-02-निविदा सं.-टीकेडी-38-2025, कार्य का नाम व स्थान-"विद्युत लोको के गियर केस, हेलिकल स्प्रिंग, बोगी एवं उसके पादर्स को खोलने, उनकी सफाई एवं पेंटिंग का कार्य" मात्रा-शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार, अनुमानित लागत (रु.में)-43,38,924.90, बयाना राशि (रु.में)-86,800, समापन अवधि-36 माह, क्र.सं.-03-निविदा सं.-टीकेडी-39-2025, कार्य का नाम व स्थान-"मोडीफाइड लेबरिंग टैक सहित थी फेस इलेक्ट्रिक लोको के ट्रैक्शन मोटर (6एफ आर ए 6068) के रिपेयर / रीकंडीनिंग का कार्य" मात्रा-450 ना, अनुमानित लागत (रु.में)-20,65,73,805.00, बयाना राशि (रु.में)-11,82,900, समापन अवधि-36 माह, क्र.सं.-04-निविदा सं.-टीकेडी-40-2025, कार्य का नाम व स्थान-"विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद के 3- फेस लोको इक्विपमेंट की एक्विटिविटी के आधार पर 02 वर्षों हेतु अंकपेंटिंग, डिसमेंटलिंग स्ट्रिपिंग का कार्य" मात्रा-शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार, अनुमानित लागत (रु.में)-75,96,005.93, बयाना राशि (रु.में)-1,51,900, समापन अवधि-24 माह, उपरोक्त सभी निविदाओं (क्र.सं. 01-04) के निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)-शून्य, उपरोक्त सभी निविदाओं (क्र.सं. 01-04) की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/ समय-23.01.2026 को 15:00 तक। नोट- 1. ई-निविदा प्रपत्र एवं ई निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट: www.ireps.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। 2. इस ई-टेंडर के लिए कोई मैनुअल ऑफ्नर मान्य नहीं है तथा ऐसा कोई मैनुअल ऑफ्नर प्राप्त होता है तो भी वह मान्य नहीं होगा। 3. इस टेंडर से सम्बंधित कोई आवश्यक संशोधन यदि जरुरी हो तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। 4. टेंडर (निविदादाता) के पास क्लास-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तथा IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। (हस्ता.) वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (टीआरएस) वि.लोको शेड, परने,तुगलकाबाद-नई दिल्ली-110044

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

आवास परियोजनाओं से पुलिसकर्मियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

सातारा। राज्यभर के प्रत्येक जिले में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवारों के लिए अत्यंत सुंदर एवं गुणवत्तापूर्ण आवास परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। इन आवासों में विविध सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुलिसकर्मियों के लिए इस प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले घरों के निर्माण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि ये गुणवत्तापूर्ण आवास पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। सातारा में वृंदावन पुलिस टाउनशिप तथा शाहपुरी पुलिस स्टेशन की नई इमारत का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



के हाथों किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री एवं पालकमंत्री शंभूराज देसाई, लोक निर्माण मंत्री छत्रपति शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, विधायक शशिकांत शिंदे, महेश शिंदे, अतुल भोसले, मनोज घोरपड़े, पुलिस महानिदेशक एवं महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण महामंडल की प्रबंध निदेशक अर्चना त्यागी, संभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोल्हापुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिला कलेक्टर संतोष पाटिल, पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नगराजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैशाली कडूकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अतुल सबनिस सहित विरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सातारा में पुलिस अधिकारियों एवं शासकीय कर्मचारियों को लिए निर्मित वृंदावन पुलिस टाउनशिप

में कुल 698 प्लॉट हैं। इस टाउनशिप में आवास, व्यायामशाला, पुस्तकालय, बहुउद्देशीय सभागृह, पावर हाउस जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस उत्कृष्ट परियोजना के लिए पुलिस आवास महामंडल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया था कि पुलिसकर्मियों को अच्छे घर मिलें। इसके लिए पुलिस आवास एवं कल्याण महामंडल को अधिकार दिए गए, पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई और पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आवास निर्माण शुरू किया गया। पुराने पुलिस लाइनों में रहने वाले पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता था। पुलिस परिवारों के जीवन में सुख-शांति लाने और उन्हें रहने योग्य घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह

संजय राऊत, राहुल गांधी के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली मात्र

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावकर ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे दिया है। संजय राऊत और उनके नेताओं ने कई उम्मीदवारों को खुलेआम धमकाने का काम किया है। झूठ बोलने में माहिर संजय राऊत अब झूठा नैरेटिव फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जब तक उम्मीदवार स्वयं हस्ताक्षर कर नामांकन वापस नहीं लेता, तब तक फॉर्म वापस नहीं माना जाता- तो इसमें आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) का क्या संबंध है? आप खुद भी तो 'पिछले दरवाजे' से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर आपको यह सब मालूम नहीं है क्या? वाघमारे उपनाम का दुरुपयोग कर किसी पर हमला करना क्या उचित है? संजय राऊत चुनाव आयोग को धमकाने जैसा गैर-जिम्मेदाराणा व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे जनता के बीच जाकर काम करें। महायुति के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर जनता की सेवा कर रहे हैं। संघ का कार्यालय महाराष्ट्र और नागपुर

में है और पूरा कामकाज मराठी भाषा में चलता है। धमकी देने का काम संजय राऊत करते हैं। एक महिला को फोन पर दी गई धमकी देश ने देखी और सुनी है। राज्य के कई हिस्सों में अबाठा गुट के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़कर अपक्ष उम्मीदवार के रूप में नामांकन



हो चुके दल' पर बात नहीं करेंगे, और आज उसी दल के साथ उन्हें जाना पड़ रहा है। मनसे के 7 नगरसेवकों को किसने तोड़ा था? दल तोड़ने की शुरुआत सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने ही की थी। मनसे की पीठ में खंडर घोपने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। यदि नगरसेवक निर्विरोध चुने जा रहे हैं, तो यह जनता के विश्वास का प्रमाण

भरा है। 'इस्तेमाल करो और फेंक दो' यही उद्धव ठाकरे की नीति रही है। भाजपा का कार्यकर्ता निष्ठावान होता है और विचारधारा के लिए काम करता है। भाजपा के जो भी बागी उम्मीदवार हैं, वे आज शाम तक अपने नामांकन वापस ले लें। आज शाम तक कई अपक्ष उम्मीदवार भी अपना नामांकन वापस लेंगे और पार्टी नेतृत्व सभी की नाराजगी दूर करेगा।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा माल लदान में उल्लेखनीय वृद्धि

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के कुशल नेतृत्व में माल लदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वडोदरा मंडल के परिचालन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर, 2025 तक कुल 10.38 मिलियन टन माल लदान किया गया है, जिससे 1288.70 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड, बाजवा साइडिंग पर उर्वरक लदान ने नया मील का पत्थर स्थापित किया है। जनवरी, 2025 में 48 रैक की पूर्व उपलब्धि को पार करते हुए दिसंबर माह में 50 रैक लोड किए गए, जिससे उर्वरक क्षेत्र के विस्तार को बल मिला है। गौठनगांव में मेसर्स कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड साइडिंग पर कंटेनर लदान में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पूर्व में इस साइडिंग पर से अधिकतम 58 रैक लोड किए गए थे, जबकि दिसंबर माह में 64 रैक लोड



जो लगभग दोगुनी है। मंडल पर माल लदान में बढ़ोत्तरी के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के अंकलेश्वर - राजपिपला रेल लाइन पर गुमानदेव स्टेशन अब माल ढुलाई के लिए खुल गया है। गुमानदेव गुड्स शेड के नए बने गुड्स प्लेटफॉर्म पर

पहली इंडस्ट्रियल नमक की रैक मिलने के साथ वडोदरा मंडल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गुमानदेव पर 650 मीटर लम्बे एक नए गुड्स प्लेटफार्म का कार्य प्रगति पर है और

एक अतिरिक्त लूप लाइन भी प्रस्तावित है। प्लेटफॉर्म के निर्माण के बाद, जल्द ही यहाँ से भविष्य में फर्टिलाइज़र की ढुलाई भी शुरू होने की उम्मीद है। मंडल पर गुड्स ट्रेनों की गति में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे माल परिवहन में समय के बचत संभव हुई है।

सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा- सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद मरीज को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क, प्रभावी और बिना किसी परेशानी के उपचार मिलना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबिटकर ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना से संबद्ध कोई भी निजी अथवा शासकीय अस्पताल किसी भी कारण से मरीज के उपचार से इनकार न करे। मंत्रालय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना से संबद्ध निजी एवं शासकीय अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर बोल रहे थे। बैठक में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिला परिमंडल के



सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने कहा कि आम और जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार जन आरोग्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन

शासन के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। हालांकि, राशन कार्ड की मूल प्रति उपलब्ध न होने या अन्य छोटे-मोटे कारणों से मरीजों को उपचार से

वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में डिजिटल राशन कार्ड सत्यापन के माध्यम से मरीजों को तत्काल उपचार प्रदान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने से पात्र लाभार्थियों को समय पर उपचार मिल सकेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। बैठक में सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा मरीज-केंद्रित बनाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

चुनाव 'स्वीप' पहले के अंतर्गत नवी मुंबई में दो हजार से अधिक विद्यार्थियों ने माता-पिता और परिवारजनों से मतदान की अपील करते हुए पत्र लिखे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई महानगरपालिका के चुनाव पहली बार बहु-सदस्यीय वर्ग प्रणाली के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रणाली में मतदान कैसे करना है, इसकी जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अनुरूप मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप पहल के अंतर्गत विद्यालयों में भी नवोन्मेषी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में नवी मुंबई महानगरपालिका के विद्यालय क्रमांक 36 और 122, कोपरखैरने गाँव में माता-पिता एवं रिश्तेदारों से मतदान करने की अपील करने हेतु पत्र लेखन का एक अभिनव उपक्रम राबवाया गया। इसके अंतर्गत कुल 2026 विद्यार्थियों ने पोस्टकार्ड पर पत्र लिखकर आगामी 15 जनवरी को होने वाले नवी मुंबई महानगरपालिका चुनावों में हमारे भविष्य के लिए मतदान करने की अपील अपने माता-पिता, परिवारजनों और रिश्तेदारों से की। निर्वाचन से संबंधित स्वीप गतिविधियों

के नोडल अधिकारी एवं उप आयुक्त डॉ. अजय गाडे, शिक्षा विभाग के उप आयुक्त श्री संघरतन खिल्लारे के मार्गदर्शन में तथा शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कडूस और शिक्षा विस्तार अधिकारी श्रीमती सुलभा बर्घरे के नियंत्रण में, केंद्र

में संदेशों का आदान-प्रदान मुख्यतः के महत्व के माध्यमों से होता है, जिससे पारंपरिक पत्र लेखन की पद्धति लगभग लुप्त होती जा रही है। किंतु पत्र और उनमें निहित भावनात्मक संदेश आज भी सभी के हृदय के निकट होते हैं।

के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उन्हें श्री संतोष माळेकर, विद्यालय के शिक्षकगण और समूह आयोजकों का सहयोग प्राप्त हुआ। मतदान का संदेश जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया



समन्वयक श्री जयप्रकाश सिंह एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सांखे और श्रीमती डॉली चराटकर के माध्यम से यह अभिनव मतदान-अपील पत्र लेखन उपक्रम अत्यंत उत्साह के साथ सफलतापूर्वक राबवाया गया। वर्तमान सूचना-प्रौद्योगिकी-अनुकूल युग

इसी उद्देश्य से, विद्यार्थियों को पत्र लेखन के महत्व से परिचित कराने और इस आत्मीय माध्यम के जरिए मतदान जागरूकता का संदेश फैलाने हेतु यह अभिनव पहल की गई। विद्यालय के कला-प्रेमी शिक्षक श्री प्रशांत गाडेकर ने इस उपक्रम की सफलता के लिए समन्वयक

जा रहा है। इसी क्रम में कोपरखैरने गाँव की महानगरपालिका शाला के विद्यार्थियों ने पत्र लेखन जैसे अभिनव उपक्रम के माध्यम से 15 जनवरी को हमारे भविष्य के लिए मतदान करने का सशक्त संदेश पत्रों के जरिए प्रभावी रूप से दिया है।

चिकित्सा अधिकारियों को नववर्ष की सौगात निरंतर सेवा के लिए चिकित्सा अधिकारियों को क्षमादान पत्रों का वितरण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुंबई स्थित स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के 195 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा अवधि के दौरान लंबित रहे मामलों के निराकरण के तहत 'क्षमादान पत्र' वितरित किए गए। इन चिकित्सा अधिकारियों ने पिछले 20 वर्षों से लंबित इस समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबिटकर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंत्री अबिटकर ने कहा कि चिकित्सकों को जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभानी चाहिए। सरकार आपको आपका हक देने के लिए सकारात्मक है। हाल ही में 150 चिकित्सकों को सेवा लंबितन अवधि का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुल 345 चिकित्सकों को पत्र वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष सभी पात्र चिकित्सा अधिकारियों को अगले एक माह के भीतर क्षमादान पत्र प्रदान किए जाएंगे, ऐसा मंत्री अबिटकर ने बताया। इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण चिकित्सा अधिकारियों को अनेक लाभ प्राप्त होंगे और इस निर्णय पर चिकित्सा अधिकारी



संतोष व्यक्त कर रहे हैं। वर्ष 2009 से पहले कई चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी रूप से कार्यरत थे। वर्ष 2009 में इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को शासकीय सेवा में समाहित किया गया, किंतु सेवा अवधि माफ न होने के कारण उन्हें अन्य लाभों से वंचित रहना पड़ रहा था। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारियों के संघ द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। इसके अनुरूप स्वास्थ्य मंत्री ने पारदर्शी तरीके से सभी पात्र चिकित्सा अधिकारियों की सेवा अवधि माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से अनेक चिकित्सा अधिकारियों की निरंतर सेवा मान्य होगी तथा इसके फलस्वरूप उन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक लाभ प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य प्रणाली में समर्पित सेवा प्रदान करने का संकल्प लें, क्योंकि इस

निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। नक्सल प्रभावित आदिवासी एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा सेवा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन के साथ विशेष प्रोत्साहन देने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपजिला अस्पताल तथा जिला अस्पतालों में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू की गई है तथा उपचार हेतु पात्र रोगी की संख्या बढ़ाकर 2399 कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस अवसर पर उप सचिव (केंद्र) विभाग, संयुक्त निदेशक राजेंद्र भालेराव, अवर सचिव गायकवाड, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी करोंगावकर सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सम्पादकीय

सबसे स्वच्छ शहर में जहरीला पानी, इंदौर ने फिर याद दिलाया तमगे नहीं, जान ज्यादा जरूरी

वह अपने आप में विचित्र और अफसोसनाक है कि जिस शहर को पिछले कई वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिल रहा हो, वहां दूषित पेयजल के सेवन से लोगों के मरने की खबरें आती हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और करीब दो सौ लोगों को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। खबरों के मुताबिक, भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में गंदा पानी मिल गया, जिससे पानी दूषित हो गया। लोगों ने इस पानी का सेवन शायद इसलिए भी कर लिया कि साफ और गंदे पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया था।

सवाल है कि अगर आम लोग पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति पर निर्भर हों, तो उनके पास गंदा और दूषित पानी पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है। लोगों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने गलती मानते हुए आनन-फानन में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन यह साफ है कि संबंधित महकमों की नींद तभी खुलती है, जब कोई बड़ा नुकसान हो चुका होता है।

यों, देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और इस क्रम में उनकी सेहत के साथ क्या होता है, इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। खबरों के मुताबिक, दूषित पेयजल की मार से प्रभावित इलाके में स्थानीय लोगों ने पिछले डेढ़ वर्ष से इससे होने वाली परेशानी और शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने की बात कही। मगर सरकार के कामकाज की शैली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेयजल में दूषित पानी मिलने के बाद जब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब भी अगले कई दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

इसके अलावा, पीने के पानी के पाइप लाइन से अलग गंदे पानी के निकासी की लाइन को सुरक्षित मानकों तक दूर रखने की व्यवस्था नहीं की गई, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या यह सिर्फ अक्षम अधिकारियों की अदूरदर्शिता का मामला है या फिर जानबूझ कर की गई अनदेखी का? इस तरह की लापरवाही का इलाज सिर्फ कुछ औपचारिक कदम नहीं हैं, बल्कि इसके लिए सभी स्तर पर सजगता और जिम्मेदारी की जरूरत है।

विडंबना यह है कि सरकार का मकसद प्रचार के लिए किसी शहर की स्वच्छता के तमगे हासिल करना रह गया लगता है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में अगर कुछ लोगों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा, तो इस विरोधाभासी हकीकत की पड़ताल करने की जरूरत है कि ऐसे तमगे जारी किए जाने के पैमाने क्या हैं? पीने का पानी सबसे बुनियादी जरूरत है, जिसके बिना ज्यादा वक्त तक नहीं रहा जा सकता।

सरकार देश भर में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के तहत सबको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का दावा करती है। मगर इस दावे की हकीकत अक्सर सामने आती रहती है, जब किसी इलाके में भूजल सूख जाने तो कहीं पीने के पानी के लिए लोगों के जद्दोजहद करने की खबरें आती हैं। जहां पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है भी, अगर वहां यह सेहत पर जोखिम से लेकर जानलेवा होने तक के खतरे से बची नहीं है, तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह समझना मुश्किल है कि कमियों पर ध्यान देने और पेयजल के पाइप लाइन के सुरक्षित होने की निगरानी नियमित जावाबदेही में शामिल क्यों नहीं होती, ताकि ऐसी त्रासदी से बचा जा सके।



अरावली पर रोक बरकरार, फिर भी सवाल बाकी- क्या कागजों में सिमट जाएगा संरक्षण?

अरावली पर्वत श्रृंखला एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। इस बार बहस का कारण केवल खनन नहीं, बल्कि वह नई न्यायिक स्थिति है जो सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद बनी है। न्यायालय ने बीते 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट किया है कि 21 जनवरी 2026 तक अरावली क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही एक नई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो पहले से नियुक्त समिति की रपट तथा न्यायालय की टिप्पणियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी।

न्यायालय ने यह भी कहा है कि पिछली सिफारिशें और उन पर आधारित उसकी टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेगी और अगली सुनवाई तक लागू नहीं की जाएंगी। पहली नजर में यह निर्णय सावधानी भरा, संतुलित और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विचारणीय कदम प्रतीत होता है। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कोई भी व्यवस्था लागू होने से पहले उसका

वैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी परीक्षण अवश्य हो।

फिर भी यह सवाल कायम है कि इतनी स्पष्टता के बाद भी अरावली पर विवाद और विरोध क्यों जारी है। इसका उत्तर उस गहरी दूरी में छिपा है जो नीति के इरादों और उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच बनी रहती है। कई लोगों को डर है कि यदि निगरानी और प्रवर्तन कमजोर रहा, तो कोई भी नई व्यवस्था केवल कागजों में सुशोभित होकर रह जाएगी, जबकि जमीन पर पुराने ढर्रे ही चलते रहेंगे।

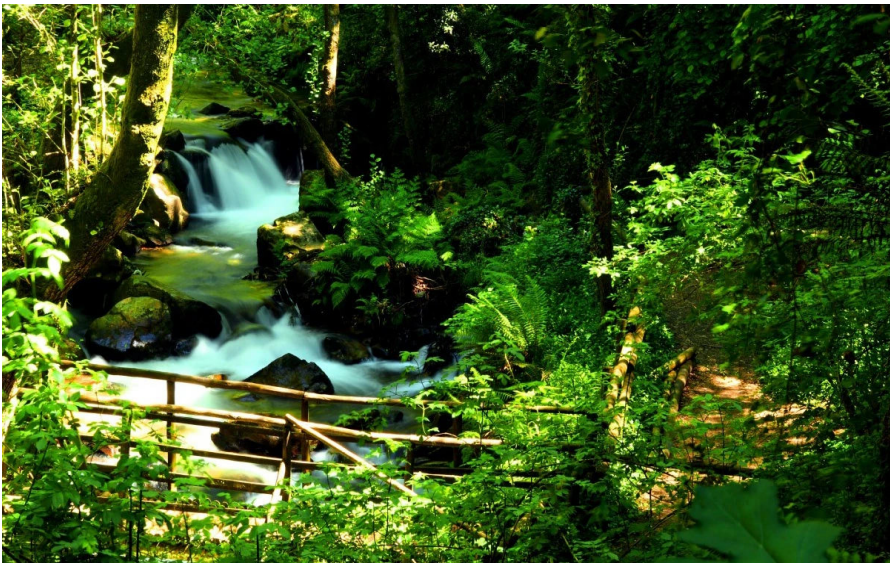
अरावली कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग दो अरब वर्ष आंकी जाती है। दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में फैली यह श्रृंखला उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ रही है। यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलवा को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाती है। इसकी चट्टानें, वनस्पतियां और घाटियां भूजल

वोट बैंक का लालच बना है पर्यावरण विनाश का कारण

वोट बैंक का लालच सत्तारूढ़ दलों को इस कदर हाथ बांधे रखने के लिए मजबूर रखता है कि बेशक प्राकृतिक आपदाओं के विनाश से लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। इसकी सरकारों को चिंता—परवाह नहीं है। लगता है उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है हर हाल में वोट बैंक को बनाए रखना। ऐसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति तब सामने आई सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूकदर्शक की तरह बैठे रहे और अदालत ने खुद मामले में सज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड देश का सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा भारी तबाही मचाती है। जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। इसका प्रमुख कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। इसमें विकास के नाम पर वनों का विनाश और वन भूमि पर अतिक्रमण प्रमुख है। पिछले आठ वर्षों में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 3, 554 लोगों की जान गई, 5, 948 लोग घायल हुए और अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ।

उत्तराखंड एक खतरनाक चक्र में फंस गया है। व्यापक और सक्रिय आपदा प्रबंधन के अभाव में, ‘देवभूमि’ (देवताओं की भूमि) प्रकृति के प्रकोप से लगातार क्षतिग्रस्त होती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दशकों से हो रही देवदार के पेड़ों की कटाई ही उत्तरकाशी में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण है। देवदार के पेड़ों की जड़े घनी



होती हैं जो मिट्टी को बांधकर रखती हैं, कटाव को रोकती हैं और भारी बारिश या भूस्खलन के दौरान मलबे और पानी के बहाव को रोककर संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। वैज्ञानिकों

होता है, जिससे आपदाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पेड़-पौधे मिट्टी को जकड़कर रखते हैं। जब पेड़ कटते हैं, तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और भारी बारिश के दौरान आसानी से बह जाती है, जिससे भूस्खलन और

का स्पष्ट मत है कि यदि धराली में ऐतिहासिक देवदार के वन क्षेत्र बरकरार रहते, तो इस आपदा का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता, या शायद नगण्य ही हो जाता।

एक समय उत्तराखंड के ऊंचे और हिमालयी क्षेत्र - विशेष रूप से समुद्र तल से 2, 000 मीटर से ऊपर के इलाके - देवदार के घने जंगलों से आच्छादित थे। प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 400 से 500 देवदार के पेड़ पाए जाते थे। वन, जो प्राकृतिक ढलानों को स्थिर रखते हैं, उनकी कमी से जल निकासी बाधित होती है और पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर

मलबा प्रवाह होता है, जैसा कि 2013 के केदारनाथ आपदा में देखा गया था।

5 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई विनाशकारी आपदा ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिमालयी राज्य की दीर्घकालिक संवेदनशीलता को उजागर कर दिया था। इस त्रासदी में 66 लोग लापता हुए। पिछले एक दशक में राज्य में लगभग 18, 464 प्राकृतिक आपदाएँ दर्ज की गईं, जिनसे भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास कई बड़ी आपदाओं से भरा पड़ा है। वर्ष 1991 के उत्तरकाशी

एक और साल बना इतिहास, यादों की गठरी के साथ समय ने फिर सिखाया- जीवन कभी ठहरता नहीं

अभिन्दन और विदाई- ये सब जीवन यात्रा के अभिन्न अंग हैं। जनवरी से दिसंबर के महीने के बीच जो भी घटित होता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, घर-परिवार, देश-विदेश से लेकर सृजन साहित्य तक, वह सब समय के साथ अपनी अवधि के भीतर घटित होकर अपने पद चिह्न मन-मस्तिष्क पर छोड़ जाता है। अमूमन हर बीता वर्ष इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। हर बार के आकलन में हम गौर करते हैं कि वैश्विक पटल पर कई घटनाक्रम हुए, जो सब कुछ समय के साथ अपना निर्धारित स्थान इस वर्ष में दर्ज करवा कर इस वर्ष में स्थायी हो गए। खेल, साहित्य, शिक्षा और तकनीक में कई उपलब्धियों ने हमें समृद्ध किया और हम सबका गौरव बढ़ाया। व्यक्तिगत संदर्भों में कई मित्र जुड़े, कई बिछड़ गए। यह जीवन का हिस्सा रहा। समय का अभाव कहीं या परिस्थितियां, सबके साथ हम चलते रहे। हम सब अपने भीतर झांक सकते हैं कि इस सबके बीच कई बार द्वंद्व रहा, उलझनें रहीं तथा समस्याएं और समाधान साथ-साथ चलते रहे।

समय की धारा में हम सब बहते चले जाते हैं, क्योंकि समय बलवान होता है। समय को हम

चाह कर भी पकड़ नहीं पाते। बल्कि यों कहें कि नहीं पकड़ सकते। समय अदृश्य है, पर चलता रहता है अनवरत। यों भी, यह किसी के रोके कभी रुका है क्या? रोकने की कोशिश करने वाले लोग रुक गए, लेकिन समय चलता रहा। हम समय के अभाव का रोना रोते रहते हैं और समय अपनी निर्धारित सीमा में अपनी चाल चलता रहता है। गांव, शहर, गलियां, व्यक्ति आदि जाने क्या-क्या अपने नवीन संदर्भों के साथ जुड़ते और छूटते चले जाते हैं। हम चुपचाप समय के साथ अपने दिन व्यतीत करते जाते हैं। समय की धारा में हर्ष, विषाद, सम्मान, पुरस्कार, अभिन्दन, सफलताएं, असफलताएं और भी न जाने कुछ हमारे जीवन का हिस्सा बन कर कभी हमें आनंद के सागर में डुबो देते हैं और कभी निराशा हमारा दामन पकड़ कर पीछे खींचती है। मगर हमारा आत्मविश्वास हमें समय के साथ कदमताल मिलाता आगे ले जाता है।

यही आत्मविश्वास मन के भीतर ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार करता है। एक नई सुबह रोज बांह पसारे सुंदर मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करती है। हम पिछला सब कुछ भूल कर फिर से नए दिन के सूरज के साथ अपने

कार्यों में तल्लीनता से संलग्न हो जाते हैं। यही हमें जीवंत बनाए रखता है। बीते वर्ष के दिसंबर ने अब हमसे विदाई ले ली है। जैसे-



जैसे हम चिंतन करते हैं इस तरह की विदाई के बारे में, अवाक हम सबके मुंह से निकलता है कि पिछले दिसंबर के बाद भी नया साल आया था और अब फिर यह पूरा हो गया। नया वर्ष अपनी नवीन रूपरेखा, नवीन गतिविधियों उपलब्धियों के साथ दस्तक दे चुका है। पता ही नहीं चला कि बीता वर्ष भी कैसे चुपके से बीत गया। बहुत कुछ नया जुड़ा, बहुत कुछ

आंखें नम हुईं। क्या यही सब फिर से इस वर्ष हमारे जीवन में नहीं दुहराएगा?

दरअसल, ये सब जीवन के अहम हिस्से हैं। इनके सहारे ही जीवन समय के साथ गतिमान रहता है। जीवन चलने का नाम है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है- ‘दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक परदा नीला झीन छिपाए है जिसमें

भूकंप में 768 लोगों की जान गई, उसके बाद 1998 के मालपा भूस्खलन (225 मौतें) और 1999 के चमोली भूकंप (100 मौतें) का नंबर आता है। साल 2013 की केदारनाथ बाढ़ सबसे विनाशकारी रही, जिसमें 5, 700 से अधिक लोगों की जान गई, जबकि 2021 की रेनी आपदा में मरने वालों की संख्या में 206 रही। पिछले एक दशक में दर्ज की गई 18, 464 घटनाओं में से चौका देने वाली 12, 758 घटनाएं भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण हुईं।

भारत में 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार, 13, 000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण है, जो कि दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है।

मध्य प्रदेश और असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, जहाँ लाखों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी मात्रा में वन भूमि अतिक्रमित है। जिससे वन, वन्यजीव और पर्यावरण को गंभीर खतरा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा देश भर में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जारी आंकड़ों के मुताबिक वन भूमि पर सर्वाधिक अतिक्रमण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश और असम सबसे आगे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य भी महत्वपूर्ण अतिक्रमण वाले राज्यों की सूची में शामिल हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) को सौंपी

एक रिपोर्ट में बताया था कि मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13, 05, 668.1 हेक्टेयर (या 13, 056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अंतर्गत था। इनमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर और दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं।

इसके अलावा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और हद्दाख ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने वन अतिक्रमण से संबंधित आंकड़े और विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की सरकारें पर्यावरण और वनों के विनाश को रोकने के लिए कितनी चिंतित हैं। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं है। कारण साफ है इससे वोट नहीं मिलते, उल्टे वन भूमि पर अतिक्रमियों को हटाने से वोट बैंक का का नुकसान होता है। यही वजह है कि सभी दल ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। इसके बावजूद कि पर्यावरण बिगड़ने से होने वाली तबाही की कीमत देश को हर साल भारी जान-माल से चुकानी पड़ती है।

से नहीं रुकता, जैसे देखते-देखते पिछला वर्ष बीत गया और अब नए वर्ष का सफर शुरू हो चुका है। कितना कुछ पीछे छूट जाता है। हम सब स्मरण करते हैं कि कल की ही तो बात है कि हमने इस वर्ष के स्वागत के लिए पलक-पांवड़े बिछाए थे। अब वह भी चला गया। हम फिर नव ऊर्जा के साथ तैयार हो जाते हैं नववर्ष के स्वागत अभिन्दन के लिए और बीते वर्ष को विदाई देने। यही सृष्टि का नियम भी है।

नूतनता सदैव वंदनीय अभिन्दनीय होती है। जीवन के विविध क्षेत्रों में जहां हमारी उपस्थिति है, वह सब बीते वर्ष के बही खाते में दर्ज हो जाता है। इसके बाद तो कैलेंडर के पन्ने और तिथियां बदल जाती हैं। कभी-कभी ऐसा अहसास होता है कि किन्तनी तेजी से समय भाग रहा है। एक वर्ष जीवन का और बीत चला अपने पीछे कितने स्मृति-चिह्न छोड़ता हुआ। कितना कुछ रह-रहकर बच आता है लोगों के साथ बिताया गया समय। वे खिलखिलाते चेहरे, वे शहर, वे जगहें, जहां हम घूमने या किसी विशेष कारण से गए, वे यात्राएं, यात्राओं के सहयात्री, यात्राओं के अविस्मरणीय पल...! कुछ भी भूल नहीं पाते, भले ही पुराना साल बीत गया हो। समय की अपनी अवधि और सीमाएं- इन सबके बीच संघर्षशील व्यक्ति गतिमान रहता है।

खनन पट्टों और पुराने पट्टों के नवीनीकरण पर रोक लगाई और एक विशेषज्ञ समिति से विस्तृत रपट मांगी। समिति ने इस बात पर बल दिया कि अब तक खनन परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रायः अलग-अलग किया गया, जबकि उनका संयुक्त प्रभाव पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर पड़ता रहा है। इसलिए समिति ने संचयी पर्यावरणीय प्रभाव के वैज्ञानिक अध्ययन, सटीक नक्शानवीसी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा और पत्थर क्షण इकाइयों पर सख्त निगरानी जैसी सिफारिशें कीं।

इसी क्रम में अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा तय करने का प्रयत्न उभरा। अलग-अलग राज्यों तथा संस्थानों द्वारा अरावली की पहचान के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाए जाते रहे हैं। इस असंगति के कारण कई क्षेत्रों में यह विवाद बना रहा कि कौन-सा इलाका वास्तव में अरावली का हिस्सा है। इस भ्रम का लाभ उठा कर खनन को वैध ठहराने की कोशिशें भी होती रहीं। इसे समाप्त करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति ने सुझाव दिया कि जो पहाड़ियां सौ मीटर से अधिक ऊंचाई रखती हैं, उन्हें अरावली की

परिधि में माना जाए। न्यायालय ने इस मानक को स्वीकार किया, लेकिन यहीं से व्यापक असहमति और विरोध शुरू हुआ।

पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली जैसी अत्यंत पुरानी और घिस कर बनी पर्वतमाला को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना उसके वास्तविक महत्त्व को कम करके देखना होगा। इस श्रृंखला की कई पहाड़ियां अपेक्षाकृत नीची अवश्य हैं, परंतु वे वर्षा जल को रोकने, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि केवल सौ मीटर की सीमा लागू कर दी जाए, तो बड़ी संख्या में ऐसी पहाड़ियां अरावली की परिभाषा से बाहर हो सकती हैं और उन पर खनन के लिए कानूनी रास्ते खुल सकते हैं। यही वह मुख्य चिंता है जिसे अब न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और इसी कारण उसने पूर्व सिफारिशों और टिप्पणियों को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है।

सरकार की ओर से यह कहा गया कि आदेशों और प्रक्रियाओं को बाहर हो सकती हैं और उन पर खनन के लिए कानूनी रास्ते खुल सकते हैं। जबकि न्यायालय ने साफ किया है कि जब तक नई उच्च स्तरीय समिति

स्वतंत्र रूप से पूरी प्रक्रिया की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक न तो सौ मीटर वाली परिभाषा लागू होगी और न ही उससे जुड़े अन्य निर्देश प्रभावी होंगे। इस प्रकार न्यायालय ने संरक्षण तथा नीति निर्माण दोनों को और अधिक वैज्ञानिक तथा पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। राज्य सरकारों की चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। अरावली चार राज्यों में फैली हुई है और हर राज्य की अपनी भूमि नीति, राजस्व संरचना और प्रशासनिक सीमाएं हैं। खनन कई राज्यों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

इसी संदर्भ में ‘अरावली ग्रीन वाल’ परियोजना का उल्लेख भी आवश्यक है। इस योजना में अरावली के आसपास बंजर भूमि को पुनर्जीवित कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दावा किया गया है कि इससे मरुस्थलीकरण पर रोक लगेगी और स्थानीय पर्यावरण सुदृढ़ होगा। मगर कई स्थानीय समुदायों को आशंका है कि इस योजना से भूमि उपयोग पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं और पारंपरिक चराई, खेती और बसावट प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो भी हो, स्थानीय

समुदायों की सहमति और सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाए। अरावली पर प्रश्न यह भी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए?

सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय इस दिशा में पुनर्विचार का अवसर है। इससे यह उम्मीद जन्म लेती है कि अरावली की रक्षा पर होने वाली बहस अब अधिक गहराई, वैज्ञानिकता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी। यदि नई समिति निष्पक्षता से सभी पक्षों की बात सुन कर संतुलित सिफारिशें करती है और सरकारें उन्हें ईमानदारी से लागू करती हैं, तो आज का विवाद कल के विश्वास में बदल सकता है। यदि प्रक्रिया फिर से केवल कागजों में सीमित रह गई और व्यवहार में वही पुरानी कमजोरियां कायम रही, तो अरावली की प्राचीन पहाड़ियां एक बार फिर कितनी कीमत चुकाने को मजबूर होंगी। यही आशंका आज की बहस का मूल कारण है और यही वजह है कि सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद असहमति की आवाज थम नहीं रही है।

पार्वती अस्पताल चौराहे के नाम आब पूर्व सांसद के नाम पर हुआ चौराहा, लोकार्पण

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। अब तक पार्वती अस्पताल चौराहे के नाम से चर्चित रहा चौराहा अब पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को चौराहे का लोकार्पण कर दिया गया। आज नगर निगम के पूर्व महापौर व पूर्व सांसद स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता के नाम पर श्याम ग्रुप कार्यालय के पास स्थित चौराहा का नामकरण व लोकार्पण एक भव्य कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर उमेशचन्द्र गणेश केशरवानी के कर कमलों द्वारा किया गया।

उद्घाटन करते हुए महापौर गणेश केशरवानी ने कहा कि स्वर्गीय श्यामाचरण गुप्ता जी का सपना प्रयागराज के गौरव के आधार पर प्राचीन संस्कृति से जोड़ते हुए आधुनिक बनाना था और आज नगर निगम द्वारा

प्रयागराज को गौरवशाली बनाने का काम हो रहा है, यह सब उनकी प्रेरणा से ही हो रहा है।

कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित अतिथियों का माल्यार्पण और शाल भेंट करके श्यामाचरण गुप्ता जी की धर्मपत्नी श्रीमती जमुनोत्री गुप्ता व श्याम ग्रुप के विदुष अग्रहरि ने किया।

इस अवसर पर उपस्थित व्यापारी नेता विजय गुप्ता ने बताया कि लोकार्पण समारोह में पूर्व सांसद डाक्टर रीता बहुगुणा जोशी,



श्रीमती केशरी देवी पटेल ने स्वर्गीय गुप्ता जी जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी राजेश अग्रहरि डॉ के.पी. श्रीवास्तव, एम एल सी संजय गुप्ता, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, नीरज त्रिपाठी पूर्व महाधिवक्ता विकास गुप्ता विधायक सुधीर हलवारिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन संजय गुप्ता, जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, काशी प्रांत उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता आर्य इंटर कॉलेज प्रबंधन, पूर्व विधायक कलेक्टर पांडे सभी ने कहा

कि प्रयागराज में विकास के साथ युवाओं के रोजगार के लिए किए गये कार्यों की सराहना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, कार्यक्रम का संचालन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया।

इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सर्वश्री विभव अग्रहरि, दीपिका अग्रहरि, प्रमिल केशरवानी, दिग्विजय अग्रहरि, सतीश चंद केशरवानी, राकेश सिंह, अनू भैया, शिव कुमार वैश्य, शारदा अग्रहरि, कुल भास्कर अग्रहरि, लल्लू लाल कुशवाहा, शिव सेवक सिंह, आनन्द विडियल्स, भोला तिवारी, नेम यादव, नीरज गुप्ता, किरण जायसवाल, गुलाब चमार, अश्वनी जैन, गिरी बाबा, संजय सिंह, डॉ बी के सिंह, रईस चंद शुक्ला, प्रवीण मालवीय, सुनील अग्रहरि, प्रमोद गुप्ता, धर्मेन्द्र अग्रहरि, संजय अग्रहरि आदि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मेला क्षेत्र में धुंध-कोहरे के बीच नाले में पलटी कार

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह धुंध और कोहरे की वजह से एक कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कार में सवार पिता-पुत्र को हल्की चोट आई। राहगीरों व आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार कराया। गोविंदपुर के कैलाशपुरी निवासी विनोद गुप्ता होलामढ़ ब्लॉक में एपीओ मनरेगा के पद पर कार्यरत हैं। उनकी मां शकुंतला देवी माघ मेला में कल्पवास



मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। खेलो प्रयागराज महापौर का कप टूर्नामेंट का आयोजन खेल गांव पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें चार टीमों ने प्रतिभाग किया। ग्रुप ए में प्रथम मुकाबला मीडिया 11 तथा भाजपा महानगर प्रयागराज 11 के मध्य हुआ जिसमें भाजपा महानगर की टीम ने मीडिया 11 की टीम को 10 विकेट से परास्त किया। पहले खेलते हुए मीडिया 11 की टीम ने 10 ओवर में 95 रन बनाए जिसका पीछा करते हुए कप्तान संजय गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा महानगर प्रयागराज 11 की टीम ने यह लक्ष्य बिना कोई विकेट खोए तीन ओवर दो गेंद में प्राप्त कर लिया। दूसरे ग्रुप का मैच महापौर 11 तथा नगर आयुक्त 11 के मध्य खेला गया। पहले खेलते हुए महापौर 11 की टीम में

10 ओवर में 122 रन बनाए इसका पीछा करते हुए नगर आयुक्त 11 की टीम 87 रन पर ही सिमट कर रह गई।

फाइनल मैच प्रयागराज भाजपा महानगर 11 तथा महापौर 11 के मध्य खेला गया। टॉस जीत



सुधांशु त्रिपाठी मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए जिन्होंने 12 गेंद पर शानदार 50 रन बनाये। मैन ऑफ द सीरीज गौरव सिंह को मिला जिन्होंने दोनों पारियों में 72 रन बनाए तथा 7 विकेट लिए।

आज मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी, महापौर उमेश चंद गणेश केशरवानी, अभिन्न श्याम गुप्ता व अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रयागराज महानगर भाजपा 11 की टीम के कप्तान संजय गुप्ता व अन्य टीम को ट्रॉफी दी गई। प्रयागराज महानगर 11 के कप्तान संजय गुप्ता ने कहा कि यह सफलता संपूर्ण टीम की प्रदर्शन को जाता है सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भाजपा महानगर प्रयागराज 11 टीम की तरफ से सांसद प्रवीण पटेल, अरुण पटेल ने भी बल्लेबाव गेंदबामें शानदार प्रदर्शन किया।

जंक्शन पर सिविल लाइंस साइड से प्रवेश बंद होने से परेशान हुए यात्री

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज जंक्शन पर की गई यातायात व्यवस्था यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। शुक्रवार सुबह से ही जंक्शन के सिविल लाइंस साइड से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को अनावश्यक घूमकर सिटी साइड से स्टेशन पहुंचना पड़ा। सुबह करीब आठ बजे जैसे ही सिविल लाइंस साइड के दोनों प्रवेश द्वार बंद किए गए वैसे ही यात्रियों की भीड़ वहां एकत्र होने लगी। यात्रियों का कहना था कि जब स्टेशन परिसर में भीड़ नहीं है तब भी नो इंट्री लागू करना समझ से परे है।

जंक्शन पर व्यवस्था के तहत यात्रियों को सिटी साइड से ही प्रवेश दिया गया, जबकि सिविल लाइंस साइड को केवल निकासी के लिए खोला गया। सिविल

लाइंस साइड से प्रवेश न मिलने के कारण दिन भर यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस होती रही। यात्रियों का कहना था कि हर बार स्नान पर्व के नाम पर एकतरफा व्यवस्था लागू कर दी जाती है, जबकि वास्तविक भीड़ की स्थिति को नहीं देखा जाता। जंक्शन पर यात्रियों को सिटी साइड से ही प्रवेश दिया जाता रहा। अनारक्षित



भूरा मठ में अन्नक्षेत्र और वस्त्र का वितरण

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। सेक्टर छह स्थित डूंग महाराज संस्थान (भूरा मठ) में अनवरत अन्नक्षेत्र का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा संत समाज को गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है।

मठ के व्यवस्थापक आचार्य आदर्श मिश्र और निखिल ने बताया कि दंडी स्वामी समाज के प्रवक्ता विद्यामार्तंड अरविंद स्वामी जोशी के निर्देशन में प्रतिदिन हजारों लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसके अलावा पक्षियों को दाना खिलाया जाता है। पिछले 134 वर्षों से माघ मास में संगम की रेतौली थरती पर संत समाज के बीच राशन और गर्म वस्त्र वितरित किया जाता है। भूरा मठ की तरफ से दंडी स्वामी नगर के शिविरों में भी लगातार धर्मार्थ कार्यों के लिए राशन पहुंचाया जा रहा है। अरविंद स्वामी ने बताया कि मठ का मकसद स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर नित नई पहचान मिले।



कठौली में दिव्यांग, विधवा व असहायों को कंबल वितरण जरूरतमंदों के साथ खड़ी है प्रयाग उत्थान समिति : डॉ. उदय प्रताप सिंह

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, कठौली, मेजा रोड में प्रयाग उत्थान समिति के तत्वावधान में दिव्यांग, विधवा एवं असहाय लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयाग उत्थान समिति के अध्यक्ष डॉ. उदय प्रताप सिंह रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रयाग उत्थान समिति का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। उन्होंने कहा, ‘समिति का प्रयास है कि कोई भी गरीब और जरूरतमंद ठंड, भूख या अभाव के कारण परेशान न हो। मानव सेवा ही हमारा धर्म है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सुख-दुख में प्रयाग उत्थान समिति हमेशा कंधे

से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।’ कार्यक्रम में समिति के महासचिव अभिषेक सी. सिंह एवं डॉ. अनुराग सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान कठौली हेमंत शर्मा, माधो प्रसाद मिश्र, जितेंद्र शर्मा, जय प्रकाश, दया शंकर



योग, ध्यान, यज्ञ, भक्ति संगीत, गंगा आरती, सत्संग और विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन विश्व के अनेक देशों से आये प्रतिभागी ले रहे आध्यात्मिक विधाओं का आनन्द

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज/ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन में आयोजित पौंच दिवसीय न्यू ईयर रिट्रीट एक आध्यात्मिक आह्वान है। यह रिट्रीट उस क्षण का साक्षी है जब नया वर्ष घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि चेतना के जागरण से आरंभ होता है। हिमालय की गोद में, माँ गंगा के पावन तट पर, यह आयोजन मानव जीवन को उसके मूल उद्देश्य, शांति, संतुलन और करुणा से पुनः जोड़ने का सशक्त माध्यम है।

इस पौंच दिवसीय रिट्रीट में योग, ध्यान, वैदिक यज्ञ, भक्ति संगीत, दिव्य गंगा आरती, प्रेरक सत्संग और विविध आध्यात्मिक गतिविधियों का समन्वित आयोजन किया गया। वरिष्ठ योगाचार्यों के

विशेष मार्गदर्शन में प्रत्येक सत्र केवल अभ्यास नहीं, बल्कि अनुभव है, ऐसा अनुभव जो प्रतिभागियों को बाहरी शोर से निकालकर भीतर की शांति से साक्षात्कार कराता है। प्रातःकालीन योग और ध्यान सत्रों ने शरीर, मन और प्राण के संतुलन को साधा, वहीं वैदिक मंत्रों के साथ सम्पन्न यज्ञ ने वातावरण को ऊर्जा, पवित्रता और सकारात्मकता से ओतप्रोत कर दिया।

पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि नया वर्ष आत्मा से जुड़ने का निमंत्रण है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में शांति, विलास का माध्यम नहीं, बल्कि आवश्यकता है। योग और ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं, जबकि भक्ति हमें अहंकार से मुक्त कर प्रेम की ओर

ले जाती है। इस नववर्ष में स्वयं को समय दें, मौन को अपनाएं और प्रकृति का सम्मान करें। जब हम अपने भीतर प्रकाश जगाते हैं, तभी हम विश्व में शांति और करुणा का दीप



प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने यांत्रिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे एक अनुभवी शिक्षाविद् हैं और शिक्षण के क्षेत्र में उनके पास लगभग 36 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने पिछले चार दशकों की विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के साथ कार्य किया है, जिससे उन्हें शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधारों का अच्छा अनुभव है।

पिछले चार वर्षों में प्रो. श्रीवास्तव ने संस्थान में मुख्य वार्डन तथा डीन, छात्र कल्याण जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। डीन, छात्र कल्याण के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने

विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्ति विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक एवं मानसिक कल्याण केंद्र की स्थापना की। डिजिटल युग में बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने की दिशा में यह पहल छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने ‘जिज्ञासा क्लब’ की शुरुआत की, जिसके माध्यम से छात्र-मैटर प्रणाली द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता के अध्ययन और शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया। यह पहल छात्रों में नैतिक मूल्यों, आत्मअनुशासन और



जीवन-दृष्टि के विकास में सहायक रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्मयोगी पोलर की परिकल्पना से प्रेरित होकर, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग की टीम शिक्षा सुधारों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी सेमेस्टर में छात्रों को परामर्श दिया जाएगा कि वे अपनी आंतरिक शक्ति के विकास हेतु हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीरामचरितमानस एवं श्रीमद्भगवतम् का अध्ययन आधुनिक डिजिटल तकनीकों के साथ करें।

डिजिटल डिटॉक्सिकेशन आज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसे कर्मयोगी सिद्धांतों के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह पहल नई पीढ़ी के छात्रों में मानसिक संतुलन, एकाग्रता और स्वस्थ जीवनशैली विकसित करेगी तथा उन्हें भारत 2047 के राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक सक्षम बनाएगी।

माघ मेला क्षेत्र में भूमि न मिलने पर भड़के पुरोहित, आंदोलन की चेतावनी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेले में जमीन आवंटन को लेकर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने मेला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। प्रयागवाल सभा के अध्यक्ष प्रदीप पांडेय ने बताया कि अधिकारियों ने उनसे प्रयागवाल नगर बसाने और पहचान पत्र देने जैसे बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन हकीकत में उन्हें अब तक जगह नहीं मिली है।

इसी नाराजगी के चलते पुरोहितों ने फैसला किया है कि पहले स्नान पर्व के बाद 5 जनवरी



आचार संहिता पथक ने 4.40 लाख रुपये किया नकद जब्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2025-26 के तहत लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रशासन की सतर्कता लगातार जारी है। इसी क्रम में उड़नदस्ता (फ्लाईंग स्क्वाड) टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लाख 40 हजार रुपये की नकद राशि जब्त की है। यह कार्रवाई 1 जनवरी 2026 को शाम करीब 5.45 बजे साईबाबा चेकपोस्ट परिसर में की गई। अतिरिक्त आयुक्त एवं आचार संहिता पथक प्रमुख विष्णु डाके तथा सहायक पथक प्रमुख समीर जवरे के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता पथक क्रमांक-1 के अधिकारी दीपक हनुमान नाईक एवं उनकी टीम ने जांच के दौरान मारुति अर्टिगा कार (MH-05-EV-6667) को रोका। जांच के दौरान वाहन से कुल 4,40,000 रुपये की नकद राशि बरामद हुई। वाहन चालक की



पहचान नरेंद्रसिंह मधुकर देवरे के रूप में हुई। जब उनसे नकदी के स्रोत, उपयोग और गंतव्य से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उड़नदस्ता और वीडियो सॉर्लिस टीम ने अधिकारियों ने मौके पर नकदी की

गिनती कर पंचनामा तैयार किया। जब्त की गई राशि के संबंध में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में विधिवत प्रविष्टि दर्ज कराई गई और बाद में यह राशि महानगरपालिका के लेखा विभाग में जमा कर दी गई। इस कार्रवाई के समय प्रभाग समिति क्रमांक-2 के प्रभाग अधिकारी माणिक जाधव, बिट निरीक्षक

धनराज पाटील, आकाश भोईर, निखिल सालवे, मनोज गुज्जा, मुस्तकीम शेख, समीर जमादार सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि के दौरान अवैध नकदी लेन-देन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मोहम्मद अनस सामीउल्लाह अंसारी को भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से इस संबंध में औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।जारी नियुक्ति पत्र पर समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के हस्ताक्षर हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मोहम्मद अनस अंसारी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसूच संगठन को सशक्त बनाने के साथ-साथ जनता के हित, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे।पार्टी नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि वे संगठनात्मक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए भिवंडी में समाजवादी पार्टी को नई मजबूती प्रदान करेंगे। यह नियुक्ति 2 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और इसकी अवधि 30 जून 2027 तक रहेगी।इस नियुक्ति के बाद भिवंडी के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज



हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने

वाले भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका चुनावों में इस नियुक्ति का पार्टी को लाभ मिल सकता है।

भिवंडी पालिका चुनाव में भाजपा की बढ़त, 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, अभी तक 6 हुई सख्या



भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन राजनीतिक तस्वीर साफ होती नजर आई। अंतिम क्षणों में बदले घटनाक्रम के चलते भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इसके साथ ही भिवंडी में भाजपा के कुल 6 उम्मीदवार बिना मतदान के ही जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं। चुनाव अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न प्रभागों में अन्य प्रत्याशियों द्वारा अपने

नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव जाना तय हो गया। इस अचानक हुए राजनीतिक बदलाव से स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्याशी का भी समावेश है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम भाजपा की सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति को दर्शाता है और इसका असर आगामी महानगर पालिका की राजनीति पर पड़ेगा।निर्विरोध निर्वाचित भाजपा उम्मीदवारों में प्रभाग क्रमांक 18 अ से अश्विनी सन्नी फूटाणकर, प्रभाग क्रमांक 18 ब से दीपा दीपक

मढवी, प्रभाग क्रमांक 18 क से अबू शाह अशफाक अहमद शेख ऊर्फ लल्लन, प्रभाग 16 अ से परेश (राजू) चौधूल तथा प्रभाग क्रमांक 23 ब से भारती हनुमान चौधरी शामिल हैं। इसके एक दिन पहले प्रभाग 17 ब सुमित पाटिल निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भाजपा पदाधिकारियों ने इसे संगठन की मजबूती और जनसमर्थन का परिणाम बताया है, जबकि विपक्षी दलों के लिए इसे चुनावी झटका माना जा रहा है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन सामने आए इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की नजरें पालिका की शेष सीटों पर होने वाले चुनावी मुकामलों पर टिकी हुई हैं।

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आगामी भिवंडी मनपा चुनाव को लेकर शहर की राजनीति इन दिनों खासा गर्माई हुई है। भिवंडी पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के बैनर-पोस्टरों पर सपा विधायक रईस कासम शेख की तस्वीरें बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। शहर में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या सपा विधायक रईस कासम शेख ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया है, या फिर वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं, हालांकि अब तक विधायक की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।



सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के हालिया टिकट बंटवारे में विधायक रईस शेख के कई करीबी समर्थकों को टिकट नहीं मिलने से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते विधायक खेमे में बेंचैनी देखी जा रही है। इस बीच सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का बयान भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने दो टूक कहा है कि 'पार्टी में टिकट का फैसला संगठन करता है, न कि कोई विधायक।' उनके इस बयान को पार्टी के भीतर अनुशासन का संदेश माना जा रहा है।

राजनीतिक सूत्रों की मानें तो बीते कुछ दिनों में भिवंडी की राजनीति में अचानक बड़ा उफान देखने को मिला है। आरोप है कि सपा विधायक रईस शेख ने कांग्रेस का बी-फॉर्म हासिल कर

अपने समर्थकों को अपनी ही पार्टी के अधिकृत सपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो इसे भिवंडी की राजनीति में एक बड़ा और असामान्य घटनाक्रम माना जाएगा। भिवंडी पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में कई ऐसे उम्मीदवारों के बैनर नजर आ रहे हैं, जो भले ही अलग-अलग दलों से ताल्लुक रखते हों, लेकिन सभी पर विधायक रईस शेख की तस्वीर

पश्चिम रेलवे द्वारा वलसाड एवं हिसार के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर चलने वाली वलसाड-हिसार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की फेरों को विस्तारित किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या

04728 वलसाड-हिसार स्पेशल को 29 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04727 हिसार-वलसाड स्पेशल को 28 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 04728 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 04 जनवरी, 2026 से सभी PRS काउंटरों तथा IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ट्रेनों के लहराव समय तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में भाजपा के 15 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की है। भाजपा के प्रदेशध्यक्ष एवं विधायक श्री रविंद्र चव्हाण के विशेष प्रयासों से पार्टी के 15 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। यह भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और जनविश्वास को दर्शाता है। भाजपा के निर्विरोध निर्वाचित विजयी उम्मीदवार इस प्रकार हैं- रंजना पेणकर - वाई 26 (ब) आसावरी नवरे - वाई 26 (क)

मंदा पाटील - वाई 27 (अ) ज्योती पाटील - वाई 24 (ब) रेखा चौधरी - वाई 18 (अ) मुकुंद उर्फ विष्णू पेडणेकर - वाई 26 (अ) महेश पाटील - वाई 27 (ड) साई शेलार - वाई 19 (क) दिपेश म्हात्रे - वाई 23 (अ) जयेश म्हात्रे - वाई 23 (ड) हर्षदा भोईर - वाई 23 (क) डॉ. सुनीता पाटील - वाई 19 (ब) पूजा म्हात्रे - वाई 19 (अ) रविना माळी - वाई 30 (अ) मंदार हळबे - वाई 26 (ड) इन निर्विरोध जीतों से कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र में भाजपा की सशक्त पकड़ और विकासपरक राजनीति पर जनता की मुहर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

मुंबई निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान, फडणवीस का दावा- हिंदू और मराठी होगा अगला मेयर

मुंबई। देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर महानगरपालिका बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि मुंबई का अगला मेयर सत्तारूढ़ महायुति से होगा और वह हिंदू और मराठी होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुंबई महानगरपालिका के 227 सदस्यीय सदन के लिए मतदान 15 जनवरी को होना है, जबकि नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी दल मेयर पद को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी एक सवाल के जवाब में दी, जिससे साफ संकेत मिला कि भाजपा नेतृत्व वाली महायुति इस पद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। **बयान से क्यों बढ़ा विवाद?**



भाजपा अध्यक्ष अमित साटम के एक बयान पर सियासी हलचल मच गई। इसके बाद शिवसेना (यूबीटी) और

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे मेयर मराठी ही होगा। **महायुति का सख्त संदेश** मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान को भाजपा का सियासी दांव माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई का नेतृत्व महायुति वे पास रहेगा। इससे साफ है कि पार्टी मेयर पद को अपनी राजनीतिक पहचान और रणनीति से जोड़कर देख रही है। यह बयान चुनावी माहौल को और धार देने वाला माना जा रहा है।

अन्य नेताओं के बयान पर सफाई पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह के उत्तर

भारतीय मेयर से जुड़े बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह टिप्पणी मुंबई के संदर्भ में नहीं थी और वह पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं हैं। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि अलग-अलग नगर निगमों की परिस्थितियां अलग होती हैं और मुंबई को लेकर पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है। **चुनाव से पहले तेज होती राजनीति** 15 जनवरी को राज्य की 29 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, जिनमें बीएमसी सबसे अहम मानी जा रही है। मेयर पद को लेकर दिए जा रहे बयानों से साफ है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और तेज होगा। सभी दल अपने-अपने समर्थकों को साधने में जुट गए हैं और मुंबई की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है।

निकाय चुनाव में भाजपा ने बदली रणनीति, मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव; यहां उतारे चार प्रत्याशी

जालना। महाराष्ट्र के जालना शहर में 15 जनवरी को होने वाले नगरपालिका चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के महायुति सहयोगी मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी उतारकर मतदाताओं तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। **भाजपा की नई पहल** अपनी पुरानी प्रथा से हटकर, भाजपा ने शहर में चार मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव पूर्व कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंट्याल के प्रभाव के कारण हुआ है। वे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। **गठबंधन में दरार और जातीय समीकरण**



गठबंधन टूट गया। जालना नगर निगम में 65 चुनावी वाई हैं। यहां मुस्लिम मतदाता कुल मतदाताओं का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हैं और वाई 2, 4, 10 और 11 में उनका निर्णायक प्रभाव है।

किस दल से कितने प्रत्याशी? अन्य महायुति सहयोगियों में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सात मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने समुदाय से 17 लोगों को नामांकित किया है। दूसरी ओर विपक्षी महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) शामिल हैं गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही है। यहां कांग्रेस

ने 51 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 19 मुस्लिम शामिल हैं। खास बात यह है कि शिवसेना (यूबीटी) ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद इस समुदाय के किसी भी नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया है। जबकि शरद पवार गुट ने दो मुस्लिम प्रत्याशियों को नामांकित किया है। **17 सीटों पर एआईएमआईएम भी लड़ेगी चुनाव** इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने जालना के मुस्लिम बहुल इलाकों में 17 स्थानों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके जिला अध्यक्ष शेख मजीद ने कहा कि लोग एक विकल्प की खोज में हैं और एआईएमआईएम उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। बता दें कि राज्य में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतों की गणना अगले दिन होगी।

इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 की मौत, मायावती बोलीं- नागरिकों के जान से खिलवाड़ करना शर्मनाक राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत

लखनऊ (एजेंसी)। प्रदेश की पूर्व सीएम एवं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से 10 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में डायरिया फैलने की वजह दूषित पीने का पानी था, जिससे कम से कम चार (सरकारी आंकड़ों के मुताबिक) मरीजों की मौत हो गई और 1, 400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कम से कम 10 मौतें होने की बात कही है। मायावती ने एक्स पोस्ट कर कहा कि इन्दौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत तथा अन्य अनेक लोगों के बीमार हो जाने की अति-दुःखद एवं चौंकाने वाली खबर काफी चर्चा में है तथा ऐसी सरकार गैर-ज़िम्मेदारी व उदासीनता को

लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आक्रोश भी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि वैसे तो लोगों को खासकर साफ हवा और पानी की मुझे हैय्या कराना हर सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, किन्तु यहाँ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की तरह ही जिससे कम से कम चार (सरकारी आंकड़ों के मुताबिक) मरीजों की मौत हो गई और 1, 400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इस प्रकार की नागरिकों के जान से खिलवाड़ करने की शर्मनाक घटना की रोकथाम के लिये राज्य सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाते रहने की ज़रूरत है। साथ ही, केन्द्र की सरकार को भी इसका उचित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाई ज़रूर करनी चाहिये ताकि देश के किसी

अन्य राज्य में ऐसी दर्दनाक घटनायें ना होने पायें। 'स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भागीरथपुरा में उल्टी-दस्त के प्रकोप से चार लोगों की मौत हुई है। हालांकि, मुझे इस प्रकोप के कारण 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। भागीरथपुरा से लिए गए पेयजल के नमूनों की शुष्कताती जांच रिपोर्ट के आधार पर इस इलाके में हज़ारों फैलने के संदेह पर महापौर ने कहा कि इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ही जानकारी दे सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बृहस्पतिवार को बताया था कि शहर के एक चिकित्सा महाविद्यालय की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा में पाइपलाइन में लीकेज के कारण पेयजल दूषित हुआ था।

सिडनी में जीत इंग्लैंड टीम के बारे में बहुत कुछ बताएगी : क्रॉली

सिडनी (एजेंसी)। इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली ने कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पांचवें एशेज टेस्ट में संभावित जीत टीम में एकता दिखाएगी, भले ही वे एशेज बरकरार न रख पाएं। पहले तीन मैच हारने के बाद इंग्लैंड को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत मिली, जिससे उन्हें खुश होने का मौका मिला। क्रॉली ने कहा, 'मुझे लगता है कि ग्रुप के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम जीत हासिल कर पाते हैं तो यह दिखाता है कि हम कितने एकजुट हैं। यह (सीरीज) हमारे पक्ष में नहीं जा सकती है, लेकिन अगर हम इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह हमारे बारे में बहुत कुछ दिखाता है।' क्रॉली ने इंग्लैंड के

तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स की भी तारीफ की, खासकर ऑस्ट्रेलिया में लंबे दो महीनों के दौरान नेट्स में उनकी र्वक एथिक और रवैये की। पॉट्स और ऑफ-स्पिनर शोएब बशीर को सिडनी में होने वाले मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। पॉट्स पूरी सीरीज के दौरान इंग्लैंड की टूरिंग पार्टी के अनयूज्ड सदस्य रहे हैं, लेकिन 2024 के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ



प्लेइंग 11 में खेलने के बाद अब 11वीं टेस्ट कैप के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'जब भी मैं उनका सामना करता हूं, वह मुझे प्रभावित करते हैं। उनके पास शेर जैसा दिल है, बहुत स्किल है और अगर उन्हें इस हफ्ते मौका मिलता है, तो वह इसके पूरी तरह हकदार हैं।' क्रॉली ने आगे चेतावनी दी कि अगर ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपने पहले

टेस्ट के लिए चुना जाता है, तो टूरिंग बल्लेबाज उन पर हमला करेंगे। मर्फी सिडनी में आखिरी एशेज मैच में खेलने की दौड़ में हैं, उन्हें एमसीजी में बॉक्सिंग डे मैच से बाहर कर दिया गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से तेज गेंदबाजों को मैदान में उतारा था। उन्होंने आखिर में कहा, 'जो भी खेलंगा, मुझे लगता है कि हमारी टीम का मंत्र यही है कि दबाव बनाया जाए। टॉड बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन मैं सोच सकता हूं कि हम उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम उनके सभी गेंदबाजों के साथ करते हैं। इसमें कुछ रिस्क होगा और अगर गेंद टर्न हो रही है, तो यह निश्चित रूप से खतरा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम उनके सभी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे।'

देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में दो साल के निचले स्तर पर : पीएमआई

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में दो साल के निचले स्तर पर आ गईं। नए ऑर्डर में धीमी वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। शुक्रवार को जारी मासिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) नवंबर के 56.6 से दिसंबर में 55 पर आ गया। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का अंक विस्तार जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन दर्शाता है।



इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की कार्यकारी निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, "वृद्धि की गति धीमी होने के बावजूद भारत के विनिर्माण उद्योग ने 2025 का समापन अच्छी स्थिति में किया। नए व्यवसायों में आई तीव्र वृद्धि से कंपनियों को वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में व्यस्त रहने की उम्मीद है और प्रमुख मुद्रास्फीति दबावों की कमी मांग को समर्थन देना जारी रख सकती है।" एचएसबीसी इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआई सर्वेक्षण द्वारा 'ट्रैक' किए गए कई मापदंडों में 2025 कैलेंडर वर्ष के अंत में वृद्धि की गति धीमी हो गई। दो वर्ष में नए ऑर्डर में

सबसे कमजोर उछाल के बीच उत्पादन वृद्धि 38 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई। कुल बिक्री में आई मंदी का एक कारण अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर में धीमी वृद्धि भी रही। नए निर्यात ऑर्डर में पिछले 14 महीनों में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया के ग्राहकों से बेहतर मांग देखने को मिली। सर्वेक्षण में कहा गया, "वर्तमान अवधि में रोजगार सृजन की गति सबसे कम रही..." कीमतों के मोर्चे पर सर्वेक्षण में कहा गया कि कच्चे माल की लागत में ऐतिहासिक रूप से नागण्य गति से वृद्धि हुई है। साथ ही, "मूल्य मुद्रास्फीति" की दर नौ महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। भारतीय वस्तु उत्पादकों को 2026 में वर्तमान स्तर की तुलना में उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है लेकिन समग्र भावना का स्तर लगभग साढ़े तीन वर्ष में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है।

सातवीं बार डकार रैली में भाग लेंगे भारतीय राइडर हरिथ नोआ

यानबू (सऊदी अरब) (एजेंसी)। भारत के अग्रणी रैली रेड राइडर हरिथ नोआ शनिवार से यहां शुरू होने वाली विश्व की सबसे मुश्किल मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिता डकार रैली में लगातार सातवीं बार हिस्सा लेंगे। केरल का यह 32 वर्षीय राइडर तीन से 17 जनवरी तक होने वाली डकार रैली में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगा। यह प्रतियोगिता छठी बार सऊदी अरब में आयोजित की जा रही है। डकार रैली में राइडर इस

बार लगभग 8, 000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसमें लगभग 4, 800 किलोमीटर में राइडर रेत के टीलों, पथरीले इलाकों और दुर्गम पठारों से होकर गुजरेंगे। इस दौरान केवल एक बार 10 जनवरी को राइडर को विश्राम करने का मौका मिलेगा। पांच बार के भारतीय राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियन नोआ ने 2020 में डकार रैली में पदार्पण किया था। तब यह रैली पहली बार सऊदी अरब में आयोजित की गई थी।



फास्टैग यूनर्स के लिए राहत एनएचएआई ने खत्म किया केवाईवी नियम

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने घोषणा की है कि अब कार, जीप और वैन जैसी चार-पहिया गाड़ियों के लिए नए फास्टैग जारी करने में 'नो योर व्हीकल' (केवाईवी) प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। यह बदलाव 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि हाईवे पर फास्टैग का इस्तेमाल अब और आसान हो जाएगा और एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी।

केवाईवी एक जांच प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि फास्टैग सही वाहन और उसके असली मालिक से जुड़ा हो। यह ड्रुकीट टैग, गलत लिंकिंग या अन्य

गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए होती है। प्रक्रिया वाहन डेटाबेस पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन विवरण की जांच करके की जाती है और यह देखा जाता है कि पहले से कोई एक्टिव फास्टैग तो नहीं है या वाहन ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। पहले फास्टैग एक्टिव होने के बाद भी कभी-कभी केवाईवी की जांच करनी पड़ती थी, जिससे यूनर्स को डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे। अब पोस्ट-एक्टिवेशन केवाईवी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।

पुराने फास्टैग वाले वाहन भी रूटीन केवाईवी से मुक्त होंगे। केवल खास मामलों में जांच की जाएगी, जैसे कि फास्टैग ढीला होना, गलत जारी होना या शिकायत मिलने पर। एनएचएआई ने तय किया है कि अब बैंक फास्टैग एक्टिव तभी कर सकेगे जब वाहन पोर्टल पर गाड़ी की पूरी जानकारी जांच ली गई हो। दुर्लभ मामलों में यदि वाहन पोर्टल पर डेटा उपलब्ध नहीं है, तो बैंक को आरसी देखकर जांच करनी होगी।

साउथ फिल्म 'डियर कॉमरेड' का बनेगा हिंदी वर्जन? रश्मिका और विजय को रिप्लेस करेंगे ये सेलेब्स

साउथ की चर्चित फिल्म 'डियर कॉमरेड' का जादू एक बार फिर चलने को तैयार है, लेकिन इस बार कहानी का फ्लेवर और चेहरे पूरी तरह से नए होंगे। साल 2019 में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी ने जिस इंटेंस लव स्टोरी से दर्शकों का दिल जीता था, अब उसी का हिंदी रीमेक बॉलीवुड में दस्तक देने जा रहा है। करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शन ने करीब 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है।

काफी समय से अनुमान लगाए जा रहे थे कि क्या इस रीमेक में भी रश्मिका और विजय ही नजर आएंगे? लेकिन ताजा रिपोर्ट्स ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने फिल्म की फ्रेश टोन को देखते हुए सिद्धांत चतुर्वेदी और प्रतिभा रांटा को मुख्य

भूमिकाओं के लिए लॉक किया है। 'थंडक 2' में सिद्धांत के गंभीर और इंटेंस एक्टिंग को काफी सराहा गया था। 'डियर कॉमरेड' के लीड कॅरेक्टर (बॉबी) की आक्रामकता और जुनून को निभाने के लिए मेकर्स उन्हें सबसे बेस्ट मान रहे हैं। वहीं 'लापता लेडीज' से अपनी

पहचान बनाने वाली प्रतिभा रांटा अपनी सादगी और इमोशनल रेंज के लिए जानी जाती हैं। फिल्म के (लिली) के इमोशनल सफर को जीने के लिए उन्हें कास्ट किया गया है।

धर्मा प्रोडक्शन के पास फिल्म के राइट्स 2019 से ही थे, लेकिन



वे सही समय और सटीक कास्टिंग का इंतजार कर रहे थे। मेकर्स का उद्देश्य इसे केवल एक 'रूटीन रीमेक' बनाना नहीं है। फिल्म की मेन कहानी के उतार-चढ़ाव को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो इसे पैन इंडिया दर्शकों के लिए और अधिक रिलेटेबल बनाएंगे। सिद्धांत और प्रतिभा की जोड़ी को चुनने के पीछे की बड़ी वजह उनका 'रॉ' और 'ऑथेंटिक' एक्टिंग है।

साउथ फिल्म में एक ऐसे छात्र नेता की कहानी थी, जो गुस्से और अपनी सोच से लड़ता है, जबकि उसकी प्रेमिका एक क्रिकेटर होती है, जो मानसिक शोषण का शिकार होती है। यह फिल्म प्यार और स्ट्रगल की कहानी है। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री को सिद्धांत और प्रतिभा पर्दे पर दिखा पाएंगे।

भारत का बंगलादेश दौरा रीशेड्यूल बीसीबी ने नई तारीखों का किया ऐलान

ढाका। बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि वे अगस्त-सितंबर 2026 में तीन मैचों की वनडे सीरीज और उतने ही टी20 के लिए भारत की मेजबानी करेंगे। बीसीबी क्रिकेट ऑपरेशन के इंचार्ज शहरयार नफीस ने बताया, 'बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीरीज पहले स्थगित कर दी गई थी, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है।' भारतीय टीम अब 28 अगस्त को आने वाली है जिसमें वनडे मैच 1, 3 और 6 सितंबर को खेले जाएंगे। टी20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे जिसके बाद पड़ोसी देश वापस घर लौट जाएंगे।

बीसीबी ने शुक्रवार को 2026 सीजन के लिए बांग्लादेश के घरेलू अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें कैलेंडर में तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत,

ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज शामिल हैं। बीसीबी ने एक बयान में कहा, 'पुष्टि किया गया कार्यक्रम बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भरे सीजन को सुनिश्चित करता है, जिससे देश भर के समर्थकों को घर पर टॉप-लेवल क्रिकेट देखने का अवसर मिलेगा, जबकि मैच स्थलों का विवरण उचित समय

पर घोषित किया जाएगा।' पाकिस्तान 9 मार्च को तीन वनडे दौरे के लिए बांग्लादेश पहुंचेगा, जो 12 से 16 मार्च के बीच खेला जाएगा। अप्रैल-मई में न्यूजीलैंड का बांग्लादेश का व्हाइट-बॉल दौरा तीन वनडे के साथ 17 अप्रैल से शुरू होगा, और उतने ही टी20, जो 27 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई को समाप्त होंगे। पाकिस्तान दो टेस्ट के लिए वापस



आया जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज का हिस्सा है। पहला रेड-बॉल मैच 8-12 मई तक और दूसरा 16-20 मई तक खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश का व्हाइट-बॉल दौरा 5 जून को तीन वनडे के साथ शुरू होगा, जिसके बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज 15-20 जून के बीच खेली जाएगी।

भारत की मेजबानी करने के बाद, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा जो चैंपियनशिप का भी हिस्सा है। टेस्ट से पहले 22-24 अक्टूबर तक तीन दिन का वार्म-अप मैच होगा। पहला टेस्ट 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा 5 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। श्रीलंका ए टीम भी मई 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जिसमें मेजबान टीम के खिलाफ दो चार-दिवसीय मैच और तीन वनडे मैच खेले जाएंगे।

विदेश में कैंसर से जूझ रहे भारत के पूर्व कोच इलाज के लिए बेटी ने लगाई मदद की गुहार

नई दिल्ली (एजेंसी)। माइकल नोब्स, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, संच्यास के बाद भारतीय हॉकी टीम के कोच भी बने थे। वे पिछले करीब पांच सालों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। माइकल को फेफड़ों का कैंसर है, जो अब उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। बीमारी के साथ-साथ उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका इलाज कराना मुश्किल हो गया है।

क्राउडफंडिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, माइकल नोब्स के इलाज के लिए एपीबेटैम नाम की एक विशेष दवा की जरूरत है, जो काफी महंगी है। केवल छह महीने के इलाज में करीब 64 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का खर्च आता है। इसी कारण उनके परिवार को लोगों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी। माइकल की दो बेटियां हैं, कैटलिन नोब्स और जैमी नोब्स।

कैटलिन खुद एक हॉकी खिलाड़ी हैं। दोनों बहनों ने 31 अगस्त 2025 को अपने पिता के इलाज के लिए एक क्राउडफंडिंग पोर्टल के जरिए मदद की अपील की। इस अभियान से करीब 75 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुटाए गए, लेकिन इसके बावजूद इलाज पूरी तरह सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। कैटलिन नोब्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता फिलहाल सिडनी में रहते हैं, जबकि वे खुद पर्थ में हैं। दोनों शहरों के बीच करीब पांच घंटे की फ्लाइट दूरी है, जिससे दूर रहकर मदद करना

और भी मुश्किल हो जाता है। पिता की सेहत को लेकर बात करते हुए कैटलिन ने कहा कि इलाज चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन माइकल नोब्स में अब भी जीने की मजबूत इच्छाशक्ति है। उन्होंने बताया कि उनके पिता को उन्हें हॉकी खेलते देखना बहुत अच्छा लगता है और इससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कैटलिन ने कहा कि हॉकी से ज्यादा उनके बीच पिता-बेटी का रिश्ता अहम रहा है और चाहे वह अच्छा खेलें या बुरा, उनके पिता हमेशा उनके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं।



संतोष ट्राफी 21 जनवरी से होगी शुरु 12 टीमों के बीच होगा मुकाबला

नई दिल्ली (एजेंसी)। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्राफी 2025-26 असम के दकुआखाना और सिलापाथर देश भर की 12 फुटबॉल टीमों के बीच 21 जनवरी से 8 फरवरी तक खेली जाएगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस महीने शुरू होने

बांटा गया है। ए ग्रुप में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, नागालैंड और राजस्थान हैं। जबकि ग्रुप बी में केरल, सर्विसेज, पंजाब, ओडिशा, रेलवे और मेघालय हैं। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दकुआखाना और सिलापाथर में खेले जाएंगे। इस



वाली संतोष ट्राफी के फाइनल ड्रा की घोषणा की है। इस चैंपियनशिप में शामिल 12 टीमों को ए और बी ग्रुप में

चैंपियनशिप की शुरुआत 1941 में हुई थी और पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी का रिकॉर्ड 32 बार खिताब जीता है।

बच्चे नहीं करने के सवाल पर फूटा बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना का गुस्सा, पत्नी के सपोर्ट में बोले, 'तैयार नहीं'

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 खत्म हो गया है और गौरव खन्ना ट्रॉफी जीतकर घर पहुंच गए हैं, लेकिन एक सवाल गौरव खन्ना और उनकी पत्नि आकांक्षा चमोला का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिग बॉस के फेमिली लोक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने उनकी पत्नी आई थी और तब ये मुद्दा उठा था कि गौरव और आकांक्षा अपनी बेबी नहीं चाहते हैं। इस वजह से वह दोनों ट्रोल हुए। मीडिया राउंड में भी गौरव से ये सवाल किया गया और अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी ये सवाल उनसे किया गया, जिसके बाद उनका गुस्सा निकला है। बिग बॉस 19 से बाहर आकर न्यूज 18 शोशा के साथ गौरव खन्ना ने खास बातचीत की है। इस दौरान गौरव ने अपनी बिग बॉस जर्नी से लेकर बच्चों को ना करने पर पत्नी आकांक्षा के ट्रोल

होने पर जवाब दिया है। गौरव ने शो से बाहर आकर कहा कि आखिर हम हमेशा यही क्यों चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमेशा ही पति को सपोर्ट

में अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ही खुश हूं। बता दें कि गौरव खन्ना की पत्नी ने बिग बॉस में आकर साफ कहा था कि वह बच्चे की

सवाल किया गया था और तब गौरव की इमोशनल साइड सामने आई थी। गौरव तब मीडिया का सवाल सुनकर रो पड़े थे और



करती रहे। क्या पति का कोई फर्ज नहीं बनता। क्या पति सपोर्टिव नहीं हो सकता? हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी पत्नी की बात से पूरी तरह सहमत हूं और

जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं और गौरव खन्ना ने नेशनल टीवी पर अपनी पत्नी का सपोर्ट किया था। याद दिला दें कि मीडिया राउंड में भी गौरव खन्ना से बच्चों पर आकांक्षा के फेंसले को लेकर

उन्होंने खुलेआम कहा था कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। तब सोशल मीडिया पर गौरव की जमकर तारीफ की थी।

भीषण सर्दी में भी अडिग है देश की सुरक्षा, राजधानी से लेकर सीमाओं तक जवानों का हौसला कायम

नई दिल्ली। देश के एक बड़े हिस्से में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तापमान लगातार गिर रहा है। ऐसे मौसम में जब आम लोग घरों में कंबलों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं, तब भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों में डटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और बर्फ से ढकी पहाड़ियों तक, सुरक्षा बलों का जज्बा इस भीषण ठंड में भी कमजोर नहीं पड़ा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो सुबह तड़के कड़कड़ाती ठंड के बीच 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। India Gate के आसपास घना कोहरा और सर्द हवाओं के बीच CRPF के जवान पूरे अनुशासन के साथ परेड अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। ठंड से बेपरवाह, सीना तान कर कदमताल

करते जवान यह संदेश दे रहे हैं कि देश की आन बान शान के सामने मौसम की कोई अहमियत नहीं। इन दृश्यों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुबह



की सर्द हवाओं और कोहरे के बीच जवान लगातार अभ्यास में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर, उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी हालात आसान नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF पूरी तरह हाई अलर्ट

पर है। सर्द रातों, ठंडी हवाएं और कम दृश्यता के बावजूद जवान हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। यहां तैनात जवानों का कहना है कि मौसम चाहे

है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, जमा देने वाली ठंड और दुर्गम रास्ते इन जवानों के हौसले को नहीं तोड़ पा रहे। इन दृश्यों में जवानों को बर्फ में चलते, इलाके की तलाशी लेते और हर खतरे से निपटने के लिए तैयार देखा जा सकता है।

देखा जाये तो चाहे राजधानी की परेड रिहर्सल हो या सीमाओं पर चौकसी और चाहे बर्फीले पहाड़ों में चल रहा सर्च ऑपरेशन, एक बात साफ है कि देश की सुरक्षा में लगे जवान हर हाल में अडिग हैं। जैसा हो, सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी जाती। सीमा की सुरक्षा हर परिस्थिति में सर्वोपरि है। हम आपको यह भी बता दें कि सबसे नही हैं। जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF पूरी तरह हाई अलर्ट

वाले इलाकों में। पीर पंजाल रेंज में तेरह हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बावजूद रोमियो फोर्स का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, जमा देने वाली ठंड और दुर्गम रास्ते इन जवानों के हौसले को नहीं तोड़ पा रहे। इन दृश्यों में जवानों को बर्फ में चलते, इलाके की तलाशी लेते और हर खतरे से निपटने के लिए तैयार देखा जा सकता है। देखा जाये तो चाहे राजधानी की परेड रिहर्सल हो या सीमाओं पर चौकसी और चाहे बर्फीले पहाड़ों में चल रहा सर्च ऑपरेशन, एक बात साफ है कि देश की सुरक्षा में लगे जवान हर हाल में अडिग हैं।

भीषण ठंड उनके हौसले को नहीं रोक सकती। यह तस्वीरें और दृश्य देशवासियों को यह एहसास कराते हैं कि हमारी सुरक्षित नींद के पीछे, किसी न किसी मोर्चे पर कोई जवान ठंड से लड़ते हुए डटा हुआ है।

माघ मेले में आयुर्वेद का महायज्ञ

श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की रक्षा को खुले आयुर्वेद चिकित्सालय

प्रयागराज। आस्था, सेवा और स्वास्थ्य के संगम माघ मेले में प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने एक बार फिर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में माघ मेला क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालयों का भव्य शुभारंभ किया गया, जिससे लाखों श्रद्धालुओं एवं साधु-संतों को निःशुल्क और प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किला रोड स्थित सेक्टर-3 में आयुर्वेद चिकित्सालय का उद्घाटन माननीय विधायक फाफामऊ श्री गुरु प्रसाद मोर्य एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी प्रयागराज डॉ. मनोज कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन तथा भगवान धन्वंतरि व माँ भारती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक गुरु प्रसाद मोर्य ने कहा कि 'महाकुंभ और माघ मेले जैसे विशाल आयोजनों में आयुष विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है, आयुर्वेद जन-जन के स्वास्थ्य

की रीढ़ है।' वहीं सेक्टर-5, काली मार्ग, कल्पवासी थाना के समीप आयुर्वेद चिकित्सालय का शुभारंभ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हडिया के पूर्व प्रधानाचार्य



एवं विश्व आयुर्वेद मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) जी. एस. तोमर द्वारा किया गया। प्रो. डॉ. तोमर ने कहा कि 'माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की आयुर्वेद में स्वाभाविक आस्था है। यह चिकित्सा पद्धति शरीर, मन और आत्मा-तीनों को संतुलित करती है।'

आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' के संरक्षण में माघ मेला क्षेत्र में संचालित आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों के माध्यम से श्रद्धालुओं एवं साधु-संतों को निरंतर चिकित्सा,

परामर्श एवं औषधि सुविधा प्रदान की जा रही है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि माघ मेले में अब तक चार आयुर्वेद चिकित्सालय सक्रिय हो चुके हैं, जहाँ अनुभवी चिकित्सकों की टीम द्वारा निःशुल्क उपचार एवं स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है।

इस अवसर पर आयुर्वेद मेला प्रभारी डॉ. हेमंत कुमार सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.

अशोक कुशवाहा, डॉ. संदीप पाण्डेय, डॉ. अवनीश पाण्डेय, डॉ. विवेक द्विवेदी, सतीश चंद्र दुबे, दिनेश कुमार दुबे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. एच. के. मिश्रा, संजय पाण्डेय, मुक्तेश मोहन शुक्ला, योग प्रशिक्षक अरुणेश मित्रा, शिव कुमार सहित आयुष विभाग का स्टाफ उपस्थित रहा।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मिली जमानत

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ में कथित उत्पाद शुल्क घोटाले के संबंध में जमानत दे दी है। यह राहत प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज दोनों मामलों में दी गई है। कोर्ट से जमानत फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद मिली है। हाल ही में ईडी ने शराब घोटाले में फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी।

चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में कथित तौर पर राज्य के खजाने को

₹2, 161 करोड़ से अधिक का चूना लगाया गया था। एजेंसी उन्हें इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताती है,



जिसमें कथित तौर पर रिश्ततखोरी, ऑफ-द-बुक बिक्री और लाइसेंस में हेराफेरी का एक नेटवर्क शामिल था। यह कथित घोटाला छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड

(सीएसएमसीएल) के माध्यम से संचालित होता था, जहाँ शराब बनाने वालों से अनुकूल बाजार पहुँच के बदले कथित तौर पर रिश्तत ली जाती थी।

ईडी का कहना है कि सरकारी दुकानों के माध्यम से देशी शराब अवैध रूप से बेची जाती थी और विशिष्ट लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए विदेशी शराब के लाइसेंस में हेराफेरी की जाती थी। इस मामले में कई अन्य हाई-प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं, जैसे व्यवसायी अनवर देबर, पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा और पूर्व आबकारी मंत्री क्वासी लखमा, जिन पर नियमित रूप से रिश्तत लेने का आरोप है। अब तक, ईडी इस मामले में ₹205 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है।

मोदी सरकार की 'पड़ोसी पहले' नीति हिट श्रीलंकाई नेता बोले- भारत ने संकट में दिया साथ

कोलंबो (एजेंसी)। श्रीलंका के विपक्ष के नेता और समागी जना बलवेयया (एसजेबी) के नेता सजित प्रेमदासा ने कहा है कि भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति ने श्रीलंका के लिए ठोस परिणाम दिए हैं, विशेष रूप से आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान।

कोलंबो से एएनआई को संबोधित करते हुए प्रेमदासा ने कहा कि भारत-श्रीलंका संबंधों को केवल कूटनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि साझा भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आर्थिक भविष्य से आकारित साझेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा भविष्य अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, ' और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग आपसी राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

प्रेमदासा ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान उसकी रिकवरी में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि नई दिल्ली ने अनुदान, आसान ऋण



और वित्तीय सहायता के माध्यम से 4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि भारत की मदद केवल बयानबाजी और घोषणाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि श्रीलंका के दवाविलयापन और मानवीय चुनौतियों का सामना करने के दौरान वास्तविक कार्रवाई में तब्दील हुई।

चक्रवात दितवाह के बाद भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए, प्रेमदासा ने वित्तीय सहायता, आपदा राहत के संसाधनों और आपातकालीन कर्मियों

की तैनाती सहित, प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में नई दिल्ली के त्वरित हस्तक्षेप की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी प्रशासन ने श्रीलंका की जरूरत के समय तत्काल और सार्थक सहायता प्रदान करके अपने वादे को पूरा किया है। प्रेमदासा ने कहा कि पड़ोसी पहले नीति श्रीलंका के लिए बहुत लाभदायक रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने श्रीलंकाई लोगों की बुनियादी मानवीय और विकासवात्मक आवश्यकताओं को सटीक रूप से पहचाना और उन्हें पूरा

किया। उन्होंने भारत सरकार और भारत की जनता दोनों को उनकी समर्थता और उदार सहायता के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में कोलंबो में बोलेते हुए, जयशंकर ने इस असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण दौर में अपने पड़ोसी देश के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी का वह पत्र जो मैंने सौंपा है, हमारी प्राथमिक सहायता देने की भूमिका को और मजबूत करता है और श्रीलंका के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। 2025 में द्विपक्षीय संबंधों और 2026 की संभावनाओं पर विचार करते हुए, प्रेमदासा ने कहा कि संबंध कई चुनौतियों से गुजरें हैं और लचीले बने हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घनिष्ठ सहयोग दोनों देशों को अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा।

पाकिस्तान में बस-वैन टक्कर 15 की मौत, 25 से अधिक घायल मृतकों में विश्वविद्यालय खिलाड़ी शामिल



इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बस और वैन की भिड़ंत में विश्वविद्यालय के एथलीट सहित कम से कम 15 लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बुधस्तिवार को यह जानकारी दी। यह घटना बुधवार को लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर अड्डा फकीर दी कुल्ली इलाके में घटी। फैंसलाबाद के उपायुक्त अली अकबर भिंडर के अनुसार, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एग्निमल साइंसेज (यूवीएसएस) के एथलीट एक आयोजन में भाग लेने के लिए बस से लाहौर जा

रहे थे। भिंडर ने कहा, जब बस एक संकरे रास्ते पर पहुंची, तो विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार यात्री वैन उससे भिड़ गई, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा, इस दुर्घटना में विश्वविद्यालय के छात्रों सहित लगभग 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 25 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और इस संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की।

हम तैयार हैं, ट्रंप के एक पोस्ट से ईरान में बवाल खामेनेई ने दी पूरे क्षेत्र में तबाही की धमकी

तेहरान (एजेंसी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के एक वरिष्ठ सलाहकार ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी विरोध प्रदर्शनों में किसी भी प्रकार का अमेरिकी हस्तक्षेप हमारे क्षेत्र में अराजकता का कारण बनेगा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप ने अपने दृष्टि सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं और जाने के लिए तत्पर हैं। ईरान

में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। यह अशांति बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर जनता के बढ़ते गुस्से को दर्शाती है। प्रदर्शन तेहरान में शुरू हुए, जहाँ दुकानदार राष्ट्रीय मुद्रा में आई भारी गिरावट, कमजोर आर्थिक विकास और बढ़ती कीमतों पर सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना करने के लिए एकत्र हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में मुद्रास्फीति 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो गया जब कम से कम दस विश्वविद्यालयों के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन

जारी रहने के कारण बाज़ार बंद रहे। अधिकारियों ने ठंड के मौसम के कारण सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी, जिससे देश के बड़े हिस्से में कामकाज ठप्प हो गया। पिछले 24 घंटों में, प्रदर्शन कई प्रांतों में फैल गए हैं। सीएनएन के अनुसार, कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों को ज़ख्म हुआ। ईरान की फ़ार्स समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई, उन्होंने अधिकारियों पर पत्थर फेंके और वाहनों में आग लगा दी। एजेंसी ने यह भी बताया कि कुछ सशस्त्र 'उपद्रवियों' ने इस जमावड़े का फायदा उठाया।